

# आजाद सिपाही

कुमार विश्वास झारखंड  
विधानसभा स्थापना  
दिवस के सांस्कृतिक  
कार्यक्रम में हुए शामिल



**FLORENCE**  
Group of Institutions  
(A Unit of : Haji Abdur Razaque  
Educational Society)  
Irba, Ranchi-835219 (Jharkhand)



**CHHOTANAGPUR  
PUBLIC SCHOOL**

AFFILIATED TO CBSE  
NEW DELHI  
No.: 3430699

Opp.: P.H.E.D. Office,  
Booty Road, Ranchi-834012

ADMISSION OPEN  
FOR SESSION

2023-24  
NURSERY to IX<sup>th</sup>

Separate Hostel Facility  
For Boys & Girls

BUS FACILITY AVAILABLE.

CONTACT NO. :  
98359 36571  
94311 06503  
83405 81301

एम्स का सर्वर हैक!

नवी दिल्ली। देश के सबसे महत्वपूर्ण अस्पताल दिल्ली एम्स का सर्वर बुधवार सुबह से डाउन रहा। आशंका है कि सर्वर को हैक कर लिया गया है। मरीजों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही है। इस अस्पताल में देशभर से मरीज आते हैं। ऐसे में मरीजों और एडमिन ऑफिस को इसके चलते काफी परेशानी उठानी पड़ रही है।

## राजधानी में जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या

गोलीबारी से इलाके में हड़कंप मचा, एक अन्य युवक को लगी गोली

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। राजधानी रांची में जमीन कारोबारी को अपराधियों ने बुधवार की देर शाम गोली मारकर हत्या कर दी है। यह घटना रांची के बरियातू थाना क्षेत्र स्थित एदलहात में हुई है। जहां बुधवार

## मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की टीएसी बैठक की अध्यक्षता निकाय चुनाव टला, आरक्षण रोस्टर पर कानूनी राय लेगी राज्य सरकार

● आदिवासी संगठनों का आंदोलन लाया रंग, 11 एजेंडे पर हुई चर्चा, लिये गये फैसले

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। राज्य में निकाय चुनाव फिलहाल टल गया है। झारखंड जनजातीय परामर्शदाता समिति (टीएसी) की बुधवार को हुई बैठक में निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर चर्चा हुई। इसमें कहा गया कि एस्टी सीटों पर आरक्षण के मामले में सरकार कानूनी राय लेगी। इसके बाद ही चुनाव पर कोई निर्णय लिया जाएगा। यह फैसला मंत्री को टीएसी की बैठक में लिया गया।

### टीएसी की थी तीसरी बैठक

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में टीएसी की बुधवार को तीसरी बैठक थी। इसमें 11 एजेंडे पर चर्चा के बाद फैसला लिया गया। बैठक में निकाय चुनाव में आरक्षण संबंधित मामलों के आलावा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने, लघु वन उत्पाद के संबंध में, जनजातीय भाषा में कक्षा एक से पांच तक के लिए अध्ययन और जनजातीय भाषाओं के अधिक से अधिक उपयोग पर नीति बनाने समेत अन्य मामलों पर विचार के बाद निर्णय लिया गया।

### भारत सरकार को की जायेगी अनुशंसा

बैठक में अधिकांश सदस्यों ने एकल पद पर एस्टी का आरक्षण समाप्त करने का विरोध किया और इसको लेकर कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाकर केंद्र सरकार भेजने का सुझाव दिया है। ऐसे में नगर निकाय चुनाव की तिथि को आगे बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। माना जा रहा है कि अब नगर निगम चुनाव समय पर नहीं होगा। फैसले की जानकारी के मुताबिक



### बैठक में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय

- पर्यावरण और जनजातीय संस्कृति का संरक्षण करते हुए राज्य में परिवेशीय अनुकूलन पर आधारित पर्यटन अर्थात इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जायेगा।
- लघु वन उत्पाद की खरीद-बिक्री के लिए सिटो-कान्ठ कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड कार्यरत है इसी के अंतर्गत व्यापक रूप से लघु वन उत्पाद की खरीद-बिक्री कर वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों की अधिक से अधिक आय बढ़े हो इसके लिए पहल किये जाने का निर्णय लिया गया।
- वनाधिकार अधिनियम-2006 के अंतर्गत अधिक से अधिक सामुदायिक पट्टा दिये जाने और उसमें अधिक से अधिक वन भूमि का उपयोग वन विभाग के नियमों एवं पर्यावरण के अनुकूल किये जाने पर जोर दिया गया।
- जनजातीय भाषा में कक्षा एक से पांच तक के लिए अध्ययन और जनजातीय भाषाओं के अधिक से अधिक उपयोग पर डॉ रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान के माध्यम से अध्ययन कराते हुए एक नीति बनायी जायेगी। और जनजातीय भाषाओं में अधिक से अधिक पाठ्य पुस्तकों का अनुवाद कराते हुए उसका वितरण कराये जाने का निर्णय लिया गया।
- जनजातीय भाषाओं के शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को तेज किया जाये। आवश्यकता अनुसार पद सृजन भी किया जाये।
- होड़ोपैथी आदिवासी ज्ञान परंपरा का गौरवपूर्ण हिस्सा रहा है। इसको देखते हुए इसके वैज्ञानिक विश्लेषण, अध्ययन, अनुसंधान, प्रकाशन के साथ सीएसआइआर के तरह वैज्ञानिक प्रयोगशाला बनाते हुए इसे आयुष में सम्मिलित किये जाने पर जोर दिया गया।
- जनजातीय समुदाय के युवाओं को पांच वर्ष से अधिक भुगतान अर्थात के साथ ऋण प्रदान किये जाने हेतु अन्य राज्यों के प्रावधानों का अध्ययन कराते हुए बैंकों के साथ राज्य स्तरीय बैठक कर नीति बनायी जाये।

‘द म्युनिसेपैलिटीज (एक्सटेंशन टू द सिड्डुल एरियास) बिल, 2011’ के स्टैंडिंग कमिटी की अनुशंसा ‘नगर निकाय की समिति, जिसमें जनजातीय समुदायों का प्रतिनिधित्व हो, की अनुशंसा नगर निकाय को बाध्यकारी होगी, को विलोपित करने की अनुशंसा की गयी थी। इस पर विचारोपरत उक्त प्रावधान को यथावत रखने की अनुशंसा भारत सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि जनजातीय हितों की रक्षा के प्रतिकूल कोई निर्णय नहीं

### बैठक में थे मौजूद

बैठक में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री-सह-टीएसी के उपाध्यक्ष चंपई सोरेन, विधायक-सह-टीएसी लिया जाना चाहिए। इसके अलावा यह भी निर्णय लिया गया कि झारखंड पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार नियामावली, 2022 के प्रारूप पर संबंधित विभागों एवं पक्षों से सम्यक विचारोपरत निर्णय लिया जाये।

जा रहा है कि घटना के समय उनके साथ खड़े भोला सिंह नाम के व्यक्ति को भी गोली लगी है। मिली जानकारी के अनुसार धवन राम देर शाम एदलहात चौक के पास स्थित एक पान गुमटी के पास खड़े थे, उसी दौरान दो अपराधी मौके पर पहुंचे और धवन को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। आधा दर्जन से ज्यादा गोली चलायी गयी। वहीं आनन-फानन में घायल

पता होती है? गौरतलब है कि याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने संविधान पीठ को बताया था कि गुरुवार को उन्होंने ये मुद्दा उठाया था। इसके बाद एक सरकारी अफसर को वीआरएस देकर चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया। बावजूद इसके कि पहले ही उन्होंने इसे लेकर अर्जी दायित्व की थी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी अरुण गोयल ने सोमवार

से 1996 के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त (सीइसी) टीएन शेणन की नियुक्ति के बाद किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त को अपने पूरे कार्यकाल का मौका नहीं मिला। क्या ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि सरकार को सीइसी बनाये जाने वाले व्यक्ति के जन्म की तारीख

### टीएसी की अनुसंधान अनिवार्य: चंपई सोरेन

बैठक के बाद मंत्री सह टीएसी उपाध्यक्ष चंपई सोरेन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा ‘द प्रोविजन ऑफ द म्युनिसेपैलिटीज बिल 2001’ पर स्टैंडिंग कमिटी द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर विचार करने का था। इस बिल में प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित क्षेत्र में स्थित नगर निकायों में अनुसूचित जनजाति की आबादी अधिक होने पर उसके अनुरूप मेयर अध्यक्ष या वार्ड पार्षद का पद अनुसूचित जनजाति के लिए ही आरक्षित होगा। परंतु इसके लिए टीएसी की अनुसंधान अनिवार्य है। अब आरक्षण रोस्टर पर महाविधायक से राय ली जायेगी। इसके बाद ही इस दिशा में कदम उठाये जायेंगे।

सदस्य प्रो स्टीफन मरांडी, दीपक विरुआ, दशरथ गगराई, विकास कुमार मुंडा, नमन विक्सल कोनगाड़ी, राजेश कच्छप, सोनाराम सिंको, शिल्पी नेहा तिकी, मनोनीत सदस्य विश्वनाथ सिंह सरदार, जमल मुंडा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, सचिव के श्रीनिवासन, सचिव केके सोन, सचिव हिमानी पांडे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

जमीन कारोबारी को रिम्स अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इधर मामले की जानकारी मिलते ही सदर डीएसपी, बरियातू थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे मामले की तफतीश की। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है।

## रांची विवि में 109 करोड़ के घोटाले पर राज्यपाल गंभीर, जांच का आदेश

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। रांची विवि में पिछले कुछ समय में 109 करोड़ के घोटाले को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। इस पर राजभवन गंभीर है। इसे लेकर बुधवार को राज्यपाल रमेश बैस ने रांची विश्वविद्यालय के कुलपति को इस पूरे मामले की जांच के लिए तथा अन्य जरूरी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि वह अनियमितताओं से संबंधित तथ्यों की गंभीरतापूर्वक समीक्षा करें। 109 करोड़ की सचिका खो जाने के मामले में दोषी पदाधिकारियों/कर्मियों के



विरुद्ध अविलंब प्राथमिकी दर्ज करें। राज्यपाल-सह-कुलाधिपति रमेश बैस के समक्ष रांची विवि के कुलपति डॉ अजीत कुमार सिन्हा ने तत्कालीन प्रभारी कुलपति डॉ कामिनी कुमार के

कार्यकाल में बरती गयी विभिन्न अनियमितताओं के संदर्भ में ध्यान आकृष्ट कराया। इस पर कुलाधिपति कार्यालय द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षा के बाद कुछ बिंदुओं पर प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया। बता दें कि इसी मामले पर राज्यपाल ने तटस्थ जांच के लिए डॉ कामिनी कुमार को प्रशासनिक दृष्टिकोण से रांची विश्वविद्यालय से प्रति कुलपति, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा में स्थानांतरित कर दिया था। (देखें पेज 03 भी)

## सीवी आनंद बोस ने ली बंगाल के राज्यपाल के रूप में शपथ

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी और विधानसभा के अध्यक्ष विमान बनर्जी समेत शामिल हुए तृणमूल के अधिकांश मंत्री और विधायक



शामिल नहीं हुए। बाद में शुभेन्दु ने आरोप लगाया कि ममता सरकार की ओर से शपथ ग्रहण समारोह में बैठने के लिए जो इंतजाम किया गया था उसमें भाजपा छोड़कर तृणमूल में शामिल हुए विधायकों के साथ कुर्सी लगायी गयी थी। ऐसा कर उन्हें अपमानित करने की कोशिश की गयी। इसलिए उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया। बोस भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) के 1977 बैच के केरल कैडर के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं।

विपक्ष ने किया बायकॉट कोलकाता। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेन्दु अधिकारी राज्यपाल डॉ. सीवी आनंद बोस के शपथ ग्रहण में नहीं गये। इसकी वजह समारोह में किया गया सीटिंग अरेंजमेंट था। शुभेन्दु ने टवीट कर बताया कि उन्हें विधायक कृष्णा कल्याणी और बिस्वजीत दास के बगल में बैठाया गया था, जो भाजपा के टिकट पर चुने गये थे, लेकिन बाद में टीएमसी में शामिल हो गये। इतना ही नहीं, उन्होंने ममता बनर्जी को भारत में पैदा हुआ सबसे मनुस्व नेता करार दिया। मुख्यमंत्री पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि वे भारत में पैदा हुईं अब तक की सबसे घटिया राजनेता हैं, जो शर्मनाक तरीके से सत्ता पर कब्जा हो गयीं। अगर वे ये सोचकर खुश हैं कि उनकी यह रणनीति मुझे परेशान करेगी, तो वे मुर्खों के स्वर्ग में रह रही हैं। लेकिन मैं उनकी तरह नहीं हूँ, बल्कि मैं अपनी गरिमा के लिए जागरूक हूँ।

**JCI Ranchi** CELEBRATING 25 YEARS OF EXPO UTSAV

**Expoutsav** ... A JCI EVENT

ये है रांची का त्योहार

24 25 26 27 28 November 2022

Morabadi Ground, Ranchi • 11:30 am - 9:00 pm

**JHARKHAND'S LARGEST CONSUMER FAIR**

**Starts Today!**

SPECIAL ATTRACTION

**FUN GOLA** | **FOOD COURT** | **BISTRO CAFE**

TODAY'S EVENT  
Fashion Show (6:30 pm)

Scan QR Code for Events Details

Banking Partner: The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank, The Central Bank of India, The Indian Overseas Bank, The Andhra Bank, The Karnataka Bank, The Tamil Nadu State Bank, The Andhra Pradesh State Bank, The Odisha State Bank, The West Bengal State Bank, The Punjab National Bank, The State Bank of India, The Union Bank of India, The Indian Bank,



## झारखंड के आम शहरियों की जिंदगी बदल दी एक फैसले ने

# हेमंत ने मकान नियमित करने की योजना से तैयार कर लिया नया समर्थक वर्ग

झारखंड के लगातार गरम होते राजनीतिक वातावरण के बीच यदि सरकार की तरफ से कोई लोक लुभावन फैसला होता है, तो स्वाभाविक रूप से इसके सियासी नफा-नुकसान की बात की जाने लगती है। ऐसा ही एक फैसला पिछले दिनों हेमंत सोरेन सरकार ने लिया है और कहा जा रहा है कि इस फैसले से झामुमो के लिए एक बड़ा समर्थक वर्ग तैयार हो गया है। हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के शहरी इलाकों में बनाये गये उन तमाम भवनों को नियमित करने की योजना तैयार की है, जिनका निर्माण बिना नक्शा के किया गया है। इस फैसले से करीब

नौ लाख मकानों को लाभ होगा। झारखंड सरकार की यह योजना इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे अनियमित ढंग से बनाये गये मकानों को प्रशासनिक कुदृष्टि से मुक्ति मिल जायेगी। झारखंड सरकार की यह योजना समाज के सभी वर्गों के लिए समान रूप से लाभकारी साबित होने वाली है,

क्योंकि शहरी इलाके में अपना घर तो आजकल हरेक परिवार का सपना होता है और एक आम शहरी अपने जीवन भर की कमाई लगाकर अपने सपनों का आशियाना बनाता है। पिछले कुछ वर्षों में झारखंड की यह विडंबना रही है कि यहां प्रशासन ने कोई ढंग का निर्माण तो किया नहीं, लेकिन तोड़-

फोड़ का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। शहरों में अक्सर अवैध ढंग से बनाये गये मकान को तोड़ने की खबरें सुर्खियां बटोरती रही हैं, लेकिन हेमंत सरकार की नयी योजना अब इस पर रोक लगा देगी। इसके अलावा जिन लोगों के मकान नियमित होंगे, उनका बड़ा हिस्सा झामुमो को सियासी लाभ पहुंचायेगा, इसकी संभावनाएं भी साफ दिख रही हैं। हेमंत सरकार के इस फैसले के सियासी नफा-नुकसान के साथ झारखंड के सामने आसन्न शहरीकरण की चुनौतियों का विश्लेषण कर रहे हैं **आजाद सिपाही** के विशेष संवाददाता **राकेश सिंह**।



राकेश सिंह

बात सितंबर महीने 2022 की है। रांची स्मार्ट सिटी के लिए भूमि अधिग्रहण और अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा था। धुर्वा में बन रहे स्मार्ट सिटी के लिए कई घरों को तोड़ा जा रहा था। बारिश के मौसम में भी प्रशासन को क्रूरता साफ दिखाई पड़ रही थी। गरीबों को उनके घरों से बेघर किया जा रहा था। वह खुन के आंसू रौने को मजबूर थे। एक तो बरसात और दूसरी तरफ उनसे उनका छत छिन जाना। इस अभियान से परेशान लोगों ने भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी से मुलाकात की थी। उन्हें सारी बातों की जानकारी दी गयी। बाबूलाल मरांडी खुद धुर्वा स्थित स्मार्ट सिटी के कार्यस्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने काम को रुकवा दिया था। बाबूलाल मरांडी ने इस संबंध में रांची के उपायुक्त से फोन पर बातचीत भी की थी। उन्होंने स्मार्ट सिटी के निर्माण से होने वाले 17

विस्थापित परिवारों के पहले पुनर्वास की मांग की, उसके बाद ही घरों पर बुलडोजर चलाने को कहा। मरांडी ने कहा कि अगर इन परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गयी, तो वह खुद उन परिवारों के साथ धरने पर बैठ जायेंगे। यह सिर्फ एक जगह या एक वर्ष के भीतर की बात नहीं है। झारखंड में लोगों को हर साल ऐसी मुसीबतों से गुजरना पड़ा है। बुलडोजर का मुंह गाढ़े-बगाढ़े देखा पड़ ही जाता है। उसके सामने उसे असहाय होना पड़ता है। अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने को जमींदोज होते देखा पड़ता है। नन्हे बच्चों का रोते-बिलखते देखा पड़ता है। बूढ़ी बीमार मां को खटिया समेत घर से निकाल कर बाहर रखना पड़ता है। घर की औरतों को कई बार मूछित होते भी देखा गया है। आंसू की बूंदों में समायी उसके आशियाने की टूटती हुई तस्वीर भी जमीन पर धाराशायी हो जाती है।



इस लोक लुभावन फैसले का होगा बड़ा सियासी फायदा

तरिके से बनाये गये सभी मकानों को नियमित करने की योजना तैयार की है। उन्होंने बताया कि ये सभी मकान अनियमित ढंग से बनाये गये और सरकार के फैसले ने उन्हें बड़ी राहत दी है। यह सूचना रांची के अलावा झारखंड के तमाम शहरों के उन इलाकों से लगातार मिल रही है, जहां हाल के वर्षों में बड़े पैमाने पर मकान बनाये गये हैं।

यथा है हेमंत सरकार का फैसला

हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड

के शहरों में लगभग नौ लाख अवैध मकानों को वैध करने के लिए नयी योजना बनाने का फैसला किया है। हालांकि पहले भी दो बार यह योजना लागू की गयी थी, लेकिन उसके प्रावधान इतने कठोर और उलझानेवाले थे कि उनका अपेक्षित लाभ नहीं मिला। इसलिए तीसरी बार नये सिरे से यह योजना लाने का फैसला किया गया है। सरकार की प्रस्तावित देकर अधिक से अधिक लोगों को फायदा पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। इसका फायदा प्रदेश के लगभग 40

शहरों में बिना नक्शा पास कराये मकान बनानेवाले या नक्शे का उल्लंघन कर मकान बना चुके लोगों को होगा। इस योजना का लाभ जैसे लोगों को मिलेगा, जिन्होंने 31 दिसंबर, 2019 से पहले मकान बना लिये थे। पिछली बार जब यह योजना लायी गयी थी, तो उसमें कई खामियां थीं। इस कारण लोगों ने अपने अवैध मकानों को नियमित करने में रुचि नहीं दिखायी। पहले लायी गयी योजना में तीन मंजिला मकानों तथा पांच हजार वर्गफुट तक के मकानों को नियमित करने का प्रावधान किया

गया था। इसके लिए काफी शर्तें रखी गयी थीं। अधिकतर मकान उन शर्तों को पूरा नहीं करते थे या शर्तों को पूरा करने के लिए मकान के ढांचे में काफी बदलाव की जरूरत होती। इस कारण लोगों ने अपने मकान के नियमितकरण की प्रक्रिया में रुचि नहीं दिखायी। इस बार जो योजना तैयार की जा रही है, उसमें बिना किसी पूर्व शर्त के एक निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करने पर मकान को नियमित किया जायेगा। इसके लिए कोई तोड़-फोड़ नहीं करनी होगी और न कोई जांच होगी।

## कैसे कहते हैं अवैध मकान

अवैध मकान उसे कहते हैं, जिसे बनाने से पहले उसका नक्शा नहीं पास कराया गया है या नक्शा पास करने के बावजूद उसका पालन नहीं किया गया है। झारखंड सरकार के पास अभी तक इसका सटीक आंकड़ा नहीं है कि राज्य में अवैध मकानों की कितनी तादाद है। एक अनुमान के अनुसार झारखंड में करीब नौ लाख मकान इस श्रेणी में हैं। इनमें से डेढ़ लाख तो अकेले रांची में हैं। इसके अलावा लगातार उग रही अवैध कॉलोनिंगों की स्थिति भी गंभीर है।

## इस फैसले से क्या लाभ होगा

झारखंड सरकार के इस फैसले का सबसे पहला लाभ यह होगा कि राज्य को अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर होनेवाली प्रशासनिक तोड़-फोड़ से मुक्ति मिल जायेगी। हाल के वर्षों में राज्य के कई शहरों में प्रशासनिक तोड़-फोड़ का विकृत चेहरा कई बार सामने आया है। इसलिए झारखंड विकास की दौड़ में अपने साथ बने छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के मुकाबले पिछड़ गया। झारखंड का पिछड़ापन केवल आर्थिक या सामाजिक मोर्चे पर ही नहीं रहा, बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक मोर्चे पर भी यह राज्य अपेक्षित विकास नहीं कर सका है। खास कर शहरीकरण जैसे गंभीर मुद्दे पर झारखंड में कभी कोई प्रभावी

विचार ही नहीं किया गया, जबकि हकीकत यह है कि झारखंड समेत पूरे देश में शहरी विकास की रफ्तार बेहद तेज हो गयी है। झारखंड में शहरीकरण की योजना बनानेवाले अधिकारियों की स्थिति यह है कि उनके पास न कोई विजन है और न योजना। वे बिना किसी मास्टर प्लान के झारखंड के शहरों में तोड़-फोड़ करते रहे हैं, जिससे स्थिति सुधरने की बजाय बिगड़ती रही है।

ऐसे में राज्य सरकार यदि सभी मकानों को वैध कर देगी, तो फिर उनके मालिकों के सामने अवैध बताकर मकान तोड़ने का खतरा नहीं रहेगा। वास्तव में हेमंत सरकार का यह फैसला राजनीतिक रूप से भी बेहद परिपक्व साबित होने वाला है, क्योंकि जो लोग इस योजना के लाभुक होंगे, वे सरकार के प्रति निश्चित रूप से आभारी होंगे। जैसे भी इस योजना के संभावित लाभुकों में समाज के हर वर्ग के लोग शामिल होंगे। चाहे बड़े व्यवसायी हों या नौकरीपेशा मध्यवर्ग, आड़े हों या पिछड़े, उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, मकान के प्रति प्रेम सभी को बराबर होता है। रांची के अपर बाजार इलाके की ही बात करें, तो वह जहां 60 प्रतिशत से अधिक मकान अनियमित हैं और इनके मालिक आम तौर पर झामुमो के समर्थक नहीं हैं। लेकिन इस फैसले के बाद उनके रुख में इस सरकार के प्रति थोड़ी नरमी तो आवेगी। इसलिए हेमंत सोरेन का यह फैसला सियासी नजरिये से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

## 15 सूत्री कमेटी में सभी को मिलेगा सम्मान और स्थान

# अगले सप्ताह जारी होगी प्रदेश और जिला स्तरीय 15 सूत्री कमेटी की सूची

### आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। झारखंड में बीस सूत्री क्रियान्वयन कमेटी के बाद अब 15 सूत्री कमेटी के गठन का काम भी पूरा हो गया है। इस कमेटी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई सहित विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को स्थान और सम्मान दोनों दिया जायेगा। इसके जरिये एक विशेष संदेश देने का प्रयास किया गया है। अगले सप्ताह 15 सूत्री समिति की सूची जारी कर दी जायेगी। यह समिति प्रदेश और जिला स्तर पर बनायी गयी है। पुख्ता सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि कांग्रेस, झामुमो और राजद के बीच कमेटी के सदस्यों को लेकर सहमति और बंटवारे का काम पूरा हो गया है। समिति के बंटवारे में वही फार्मूला

**प्रखंडों में कांग्रेस के करीब 11 सौ कार्यकर्ता किये गये एडजस्ट**  
बीस सूत्री क्रियान्वयन समिति के तहत प्रखंडों में कुल 11 सौ कार्यकर्ताओं को एडजस्ट किया गया है। बता दें कि बीस सूत्री क्रियान्वयन समिति का बंटवारा जिले और प्रखंड स्तर पर किया गया है। कुल 264 प्रखंडों में से कांग्रेस के हिस्से में 110 प्रखंड आवे थे। प्रत्येक प्रखंड में गठबंधन के तीनों दल के कुल नौ सदस्यों को शामिल किया गया। इसमें कांग्रेस के कुल छह सदस्य शामिल थे। यानी 110 प्रखंडों में कुल 666 कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। बचे हुए 154 प्रखंडों में से प्रत्येक में कांग्रेस के तीन सदस्य शामिल किये गये। इस हिसाब से करीब 460 कार्यकर्ताओं को प्रखंडों में एडजस्ट किया गया।

अपनाया गया है, जो 20 सूत्री के लिए अपनाया गया था। जिला स्तर पर गठित होने वाली 15 सूत्री कमेटी में चार अल्पसंख्यक कार्यकर्ता सदस्य के रूप में शामिल होंगे। इसमें मुस्लिम, इसाई, सिख समेत अन्य अल्पसंख्यक कार्यकर्ता होंगे।

**किसके हिस्से कितने जिले आये**  
पाटी जिलों की संख्या  
कांग्रेस 10  
झामुमो 13  
राजद 01

## पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को हाइकोर्ट से बड़ी राहत

# कुर्की-जब्तौ आदेश को सशर्त निरस्त किया

### आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। झारखंड हाइकोर्ट से पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता योगेंद्र साव को बड़ी राहत मिली है। हाइकोर्ट ने बुधवार को योगेंद्र साव के खिलाफ निचली अदालत द्वारा जारी कुर्की-जब्तौ के आदेश को निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने उन्हें निर्देश दिया है कि वे ट्रायल कोट के समक्ष सरेंडर कर बेल लें। झारखंड हाइकोर्ट के

न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी के कोर्ट में योगेंद्र साव की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार मिश्रा ने अदालत में पक्ष रखा। अदालत ने यह शर्त रखी है कि ट्रायल कोर्ट में अगर वह पांच दिसंबर तक उपस्थित हो जाते हैं, तो उनके खिलाफ कुर्की-जब्तौ आदेश प्रभावी नहीं होगा। दरअसल, रांची

के जगन्नाथपुर थाना में योगेंद्र साव एवं उनके बांड़ीगार्ड के खिलाफ धमकी देने का मामला दर्ज है। इस केस में रांची सिविल कोर्ट ने योगेंद्र साव के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। इसे रद्द करने के लिए उन्होंने हाइकोर्ट से गुहार लगायी थी। योगेंद्र साव फिलहाल एनटीपीसी भूमि अधिग्रहण से जुड़े आंदोलन के केस में जमानत पर हैं।

## गौरव के पल : भारतीय महिला हॉकी टीम में चार झारखंडी शामिल

# निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग करेंगी देश का प्रतिनिधित्व

### आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड की एक साथ चार हॉकी खिलाड़ियों को चुना गया है। हॉकी इंडिया के एक्सक्यूटिव डायरेक्टर आरके श्रीवास्तव ने हॉकी झारखंड के महासचिव विजय शंकर सिंह को इस बारे में खबर की है। उन्होंने बताया है कि स्पेन में 27 नवंबर से 18 दिसंबर तक आयोजित होने वाली एफआइएच महिला हॉकी राष्ट्र कप में भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड की हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस खबर पर हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह ने कहा कि झारखंड के लिए यह गौरवपूर्ण क्षण है। वर्तमान समय में भारतीय टीम में जगह बनाना बहुत बड़ी

उपलब्धि है। भारतीय महिला हॉकी टीम ओलिंपिक और विश्वकप जैसी बड़ी-बड़ी प्रतियोगिताओं में क्वालीफाई कर रही है और अच्छे पोजिशन तक पहुंच रही है। विजय शंकर सिंह ने कहा कि झारखंड से एक जमाने में तीन-चार खिलाड़ी भारतीय टीम में हुआ करते थे, परंतु बीच में सभी टीमों में झारखंड शून्य हो गया था। परंतु झारखंड के सभी लोगों ने हॉकी के विकास के लिए समर्पण और निस्वार्थ भाव से राज्य के हॉकी के विकास की सोच लेकर कार्य किया जिसका रिजल्ट अब देखने को मिल रहा है।

## ये है खिलाड़ियों की प्रोफाइल

**निक्की प्रधान** : खूंटी जिला के मोरो प्रखंड अंतर्गत पेरोल गांव में

आज तक एक खेल का मैदान नहीं बना है। यहां अपनी बड़ी बहनो से प्रेरणा लेकर नंगे पांव हॉकी की शुरुआत करते हुए निक्की आगे बढ़ीं। वह झारखंड की पहली हॉकी खिलाड़ी हैं, जो दो-दो ओलिंपिक खेल कर इतिहास रच चुकी हैं। विश्व के सभी बड़े प्रतियोगिताओं ओलिंपिक गेम्स, वर्ल्ड कप, कॉमनवेल्थ गेम, एशिया कप सहित सभी बड़े-बड़े टूर्नामेंटों में भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए कई कीर्तिमान बना चुकी हैं।

**सलीमा टेटे** : सिमडेगा जिला के सदर प्रखंड अंतर्गत बड़की छपार गांव में आज भी मोबाइल सिग्नल के लिए चट्टान या पेड़ों का सहारा लेना पड़ता है। इस गांव से कोसों पैदल चलकर या पिता सुलक्षण टेटे के साइकिल में बैठ कर विद्यालय और गांव की टीम से खस्सी कप

मुर्गा कप हॉकी प्रतियोगिताओं से हॉकी की शुरुआत सलीमा ने की। वह सिमडेगा जिला की प्रथम महिला ओलिंपियन हैं, जिसके खेल की सराहना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार कर चुके हैं। विगत तीन-चार वर्षों में ही ओलिंपिक गेम्स, वर्ल्ड कप, एशिया कप, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे कई बड़े टूर्नामेंटों में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व उसने किया है। **संगीता कुमारी** : हॉकी की नर्सरी सिमडेगा जिला के केरसई प्रखंड अंतर्गत करंगागुड़ी नवा टोली गांव में आज भी बरसात के दिनों में अपने पैर के जूते चपलों को हाथ में लेकर चलना पड़ता है। ऐसे गांव से बेहद गरीब परिवार से पल बढ़कर बांस की स्टिक और उसके जड़ से हॉकी की शुरुआत करते हुए संगीता कुमारी विगत एक वर्ष में कॉमनवेल्थ गेम,

एफआइएच हॉकी लीग में जलवा दिखा चुकी है। इससे पूर्व जूनियर एशिया कप इत्यादि कई प्रतियोगिताओं में भी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। **ब्यूटी डुंगडुंग** : सिमडेगा जिला के केरसई प्रखंड अंतर्गत खिलाड़ियों के गांव करंगागुड़ी बाजू टोली की ब्यूटी डुंगडुंग के परिवार के सदस्य पीढ़ी दर पीढ़ी अच्छे हॉकी खिलाड़ी रहे हैं। उनके परिवार में उनके दादा, पिताजी, चाचा, तीन बड़े भाई, भाभी भी राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रहे हैं। ब्यूटी विगत 2018 से जूनियर भारतीय टीम से देश के लिए खेल चुकी है। इस वर्ष पहली बार सीनियर भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए चुनी गयी है। उसके गांव में वर्षों से बन रहा आंगनबाड़ी केंद्र आज भी अधूरा है।

## 2.48 करोड़ रुपये का घोटाला मामला

# एसबीआइ के शिकारीपाड़ा ब्रांच के पूर्व मैनेजर के खिलाफ सीबीआइ करेगी जांच

### आजाद सिपाही संवाददाता

**दुमका**। दुमका जिले के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शिकारीपाड़ा ब्रांच के पूर्व मैनेजर मनोज कुमार पर और कई अज्ञात लोगों ने 2.48 करोड़ रुपये का घोटाला किया है। इस मामले की जांच अब सीबीआइ करेगी। सीबीआइ एसीबी 6(अ) 2022- मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी है। इस मामले की जांच

डीएसपी प्रह्लाद किशोर झा करेंगे। गौरतलब है कि राजमहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए पूर्व मैनेजर मनोज कुमार और कई अज्ञात लोगों ने 2.48 करोड़ रुपये का घोटाला किया है। यह घोटाला साल 2014 से 2018 के बीच किया गया है। इस दौरान मनोज कुमार एसबीआइ के सामाजिक, बरहेट, फूलबंगा और शिकारीपाड़ा में ब्रांच मैनेजर थे।

घोटाले को लेकर एसबीआइ के दुमका रीजनल बिजनेस ऑफिस के रीजनल मैनेजर ने शिकारीपाड़ा थाने में एफआइआर दर्ज करायी थी। इसके बाद भाललपुर से मनोज कुमार को गिरफ्तार किया था। **कर्ज उतारने के लिए किया था घोटाला**

कुमार ने बताया था कि वह साहिबगंज जिले के राजमहल विधानसभा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। इसके लिए उसने काफी रकम भी खर्च किया, हालांकि उनको किसी पार्टी से टिकट नहीं मिला, जबकि दूसरी ओर उनके ऊपर काफी कर्ज बढ़ गया, जिसके बाद उन्होंने रुपये घोटाला करने की घटना को अंजाम दिया।

बैंक प्रबंधन की आरंभिक छानबीन में घोटाले की रकम 1.15 करोड़ पायी गयी थी। इसी के आधार पर शिकारीपाड़ा थाने में मैनेजर पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। बाद में बैंक की छानबीन बढ़ती रही, वहीं 28 अगस्त 2022 को झारखंड सरकार ने गृह, कारा एवं आपदा विभाग ने सीबीआइ को इस केस की जांच स्वीकारने का अनुरोध किया।



## मुख्यमंत्री दिल्ली में आयोजित सांस्कृतिक संध्या में होंगे शामिल हेमंत सोरेन दिल्ली रवाना, उद्योग विभाग के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा

27 नवंबर तक आयोजित है अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला

आजाद सिपाही संवाददाता

दिल्ली/रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को देर शाम दिल्ली रवाना हो गये। अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 में गुरुवार 24 नवंबर को झारखंड राज्य दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर झारखंड के पारंपरिक नृत्य, गीत और संस्कृति से लोग रूबरू होंगे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे।

### स्वरोजगार सृजन की झांकी

ट्रेड फेयर में ना सिर्फ झारखंड के रेशमी परिधान लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, बल्कि राज्य सरकार द्वारा राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार सृजन के लिए किये जा रहे कार्यों की झांकी लोगों को आकर्षित कर रही है। मुख्यमंत्री



हेमंत सोरेन की सोच के अनुरूप मेले में कृषि, पशुपालन विभाग द्वारा जैविक कृषि का स्टाल, वन विभाग का स्टाल, जेरेडा का स्टाल, मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड के स्टाल में प्रदर्शित विभिन्न शिल्पकारों के हस्तनिर्मित लकड़ी, बांस से

निर्मित नेम प्लेट, पेन स्टैंड, टी कोस्टर, सर्विस प्लेट, मूर्ति आदि दर्शकों द्वारा बेहद पसंद किया जा रहा है। लोगों को मेले में जैविक उत्पाद और जैविक खेती आकर्षित कर रही है। मालूम हो कि 27 नवंबर तक आयोजित अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2022

में झारखंड पार्टनर स्टेट के तौर पर शामिल है। मेले में झारखंड के स्थानीय बुनकरों, ट्राइबल शिल्पकारों द्वारा प्रदर्शित पारंपरिक आदिवासी जैकेट, शर्ट्स, टॉवल, गमछा, टोपी आदि दर्शकों के द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है।

## विधानसभा में केंद्र-राज्य संबंधों पर नेशनल कांफ्रेंस, स्पीकर ने कहा- देश की सुरक्षा, स्थिरता के लिए केंद्र-राज्य का संबंध स्वस्थ होना जरूरी

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। झारखंड विधानसभा में स्थापना दिवस समारोह के दूसरे दिन बुधवार को केंद्र-राज्य संबंधों पर नेशनल कांफ्रेंस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि देश की स्थिरता, सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए स्वस्थ केंद्र-राज्य संबंध महत्वपूर्ण है। देश के विधान के समय की घटनाओं ने संविधान सभा को एक ऐसे संघवाद को चुनने के लिए प्रेरित किया, जो केंद्र की ओर थोड़ा झुका हुआ है, लेकिन राज्य को प्रगति और परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण साधन होने के नाते संविधान में शक्तियां भी दी गयी हैं। संविधान के लागू होने के बाद से पिछले सात दशकों में 105 संशोधन हुए हैं, जिनमें से कई का केंद्र-राज्य के संबंधों पर सीधा असर पड़ा है।



किया गया और स्वतंत्र भारत ने संघवाद के बदलते युग को देखा। कई राजनीतिक इतिहासकारों और संवैधानिक विशेषज्ञों ने देखा कि केंद्र सरकार के हाथों में शक्तियों का अधिक केंद्रीकरण केंद्र और राज्यों के बीच बढ़ते संघर्षों के प्रमुख कारणों में से एक था।

### कई अहम मुद्दों पर विशेषज्ञ विचार रख रहे

केंद्र-राज्य के संबंधों पर चर्चा के लिए विधानसभा में प्रो दिलीप तिवारी, प्रो मनोज कुमार सिन्हा, प्रो अनुराग दास, प्रो ए लक्ष्मीनाथ, डॉ नीरज कुमार, प्रो उदय शंकर समेत कई विशेषज्ञ जुटे थे। कांफ्रेंस में संघवाद पर न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा, केंद्र राज्य संबंध और सुशासन पर इसके प्रभाव जैसे कई अहम मुद्दों पर

विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। **विधानसभा को मिले राज्यपाल को हटाने का प्रस्ताव पास करने का अधिकार : प्रो उदय शंकर** विधानसभा में आयोजित केंद्र-राज्य संबंधों के राष्ट्रीय सम्मेलन में राज्यपाल की भूमिका और उनके कार्य पर चर्चा हुई। रायपुर के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर उदय शंकर ने कहा कि अगर राज्यपाल राज्यहित में काम न कर रहे हों, तो उन्हें हटाने का अधिकार राज्य के पास होना चाहिए। विधानसभा में प्रस्ताव पास कर उसे राष्ट्रपति के पास भेजने का अधिकार विधानसभा के पास होना चाहिए। लेकिन इसकी भी एक गाइडलाइन तय होनी चाहिए, ताकि राज्यपाल विधानसभा की कठपुतली बनकर न रह जायें। उन्होंने कहा कि हमेशा यह बात होती है कि

राज्यपाल कि नियुक्ति और उन्हें हटाने में राज्य का भी रोल होना चाहिए। **केंद्र अपने प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं** प्रोफेसर उदय शंकर ने कहा कि देशों में संघ और राज्य होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर दो सिस्टम से काम करते हैं। कमिंग टुगेदर यूएस मॉडल है, जबकि भारत में होल्डिंग टुगेदर सिस्टम में केंद्र और राज्य जुड़े हैं। भारत के संविधान में संघीय ढांचे में केंद्र को ज्यादा पावर मिला है। केंद्र अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकार होती है, तो कई बार केंद्र और राज्य में विवाद होता है। राज्यपाल पर केंद्र के एजेंट के रूप में काम करने का आरोप लगता है। ऐसे में राज्यपाल जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।

### स्वतंत्र भारत ने संघवाद के बदलते युग को देखा

उन्होंने कहा कि समय-समय पर, केंद्र-राज्य संबंधों का परीक्षण

## स्वास्थ्य सचिव को जवाब के साथ सशरीर हाजिर होने का दिया निर्देश

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। रिम्स की बदहाली और इससे जुड़े अन्य मामलों पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश डॉ

### रिम्स के मामलों पर हाईकोर्ट

रवि रंजन और जस्टिस सुजित नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने विभिन्न मामलों की सुनवाई एक

साथ की। सुनवाई के दौरान राज्य के स्वास्थ्य सचिव को 28 नवंबर को अगली सुनवाई में जवाब के साथ सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान

अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालत के आदेश के बाद भी सीधी नियुक्ति के बजाय आउटसोर्सिंग कराना अदालत की अवहेलना है।

**राशिफल**  
डॉ एंके बेरा | 9431114351

**मेघ** रोजी-रोजगार में लाभकारी वातावरण देखने, भागीदारी में खास महत्त्व का निराकरण होना।

**वृष** कारोबार में उन्नति होने की संभावना, नवीन कार्य की योजना सफल होगी।

**मिथुन** कहीं से तुम फल प्राप्त होगा, आर्थिक एवं सुदृढ़ बनाना, मित्रों से सहायता मिलेगी।

**कर्क** शत्रु प्रबल होकर लंबी लोहे, खर्च एवं निवेश रखी अन्वया कर्ज लेने की चेतावनी आ सकती है।

**सिंह** राजकीय कार्यों में सफलता मिलेगी, एड-प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, रात्रि में धन लाभ का योग बन रहा है।

**कन्या** प्रवास से कहीं कहीं पूरे होने, मेहनतों का अगमन होगा व आय उन्नति आनंदता में व्यस्त रहेगी।

**तुला** सपति संबंधी मामलों का निपटारा आपके पक्ष में होगा, कहीं से शुभ समाचार मिलेगा।

**वृश्चिक** नये-नये लोगों से संपर्क बनेगा, घर, कार्टी में व मान-सम्मान में बढ़ोतरी होगी।

**धनु** आगन्ती के खेत बढ़ेंगे, नौकर-वाकर, वाहन व नौतिक ऐडवर्ड के साधनों में वृद्धि होगी।

**मकर** अचानक धन लाभ होने की संभावना, आशातुष्ट कार्यों में सफलता मिलेगी।

**कुंभ** सरकारी नौकरी करने वालों के एड-प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, गृह-भूमि-वाहन का सुख।

**मीन** लंबित कार्य निपटारने में व्यस्तता रहेगी, नौकरी में एडवन्समेंट के अवसर भी मिल सकते हैं।

**देश-विदेश की खबरों के लिए विलक करें**  
www.azadsipahi.com

## बाबूलाल ने सीएम हेमंत सोरेन से की पुलिस नियुक्ति परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा है। इसमें कहा है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पूर्व में पुलिस नियुक्ति परीक्षा ली गयी थी। 7272 पदों के लिए परीक्षा हुई। 7000 इसमें सफल रहे। इनमें से 4882 को नियुक्ति पत्र मिल गया। शेष लगभग 2200 अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। वे अपनी

सात हजार में से 22 सौ अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला



नियुक्ति के लिए दर-दर भटक रहे हैं। कई बार आपसे (सीएम)

मिलकर भी आग्रह किया है। विज्ञापन के मुताबिक प्रथम सूची जारी करने के बाद पद रिक्त रह जाने के उपरांत एक समेकित मेधा सूची जारी होगी। इस आधार पर सभी रिक्त पदों को भरा जायेगा जिस पर अब तक काम नहीं हुआ है। सफल 2200 अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया के सभी चरणों में सफल हुए हैं। फिर भी उन्हें नियुक्ति नहीं दिया जाना नैसर्गिक न्याय के विपरीत है। ऐसे में इनकी नियुक्ति के लिए पहल हो।

## झारखंड उपहार में नहीं आंदोलनकारियों के त्याग संघर्ष, शहादत के बल पर मिला : मथुरा महतो

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। राज्यपाल के द्वारा झारखंड विधानसभा के 22वें स्थापना दिवस में झारखंड अलग राज्य को उपहार में दिये जाने के संदर्भ उभरे गये अभिभाषण का झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के मुख्य संरक्षक और टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने विरोध किया गया। कहा है कि झारखंड उपहार में मिला हुआ राज्य नहीं है बल्कि लाखों झारखंडियों के त्याग, संघर्ष व बलिदान और आंदोलनकारियों के

### राज्यपाल के बयान का विरोध

खून से बना है। ये बातें उन्होंने झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के बैठक में कही हैं। मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के कार्यकाल में तीन राज्य एक साथ बने थे। उसमें झारखंड भी एक था। आज भी हमारे वृहद अलग राज्य का सपना अधूरा है। इस अवसर पर टीएसी के सदस्य और झारखंड आंदोलनकारी विश्वनाथ सिंह सरदार

ने कहा कि झारखंड अलग राज्य की मांग 1928 में उन्नति समाज के द्वारा साहमन कमीशन के समक्ष की गयी थी। संघर्ष मोर्चा के संस्थापक पुष्कर महतो ने कहा कि राज्यपाल रमेश बैस जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी को झारखंड आंदोलन की ऐतिहासिकता, आंदोलनकारियों के संघर्ष एवं कुर्बानियों का अध्ययन नहीं है। इसलिए वे झारखंड अलग राज्य को उपहार में देने की बातें कह रहे हैं।

## कार्रवाई : रांची विवि में 109 करोड़ का घोटाला मामला इन बिंदुओं पर 15 दिनों के अंदर करनी है जांच

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। राज्यपाल ने 15 बिंदुओं पर डॉ कामिनी कुमार के संबंध में जांच कर स्पष्टीकरण देने को कहा है। वे बिंदु इस प्रकार हैं :  
1. तत्कालीन कार्यवाहक कुलपति, रांची विश्वविद्यालय, रांची के पद पर रहते हुए वर्ग तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के 36 कर्मियों को 18.12.2021 को नियमित कर दिया गया। उक्त कार्य को किस आधार पर किया गया, यह स्पष्ट नहीं है। कार्यवाहक कुलपति को ये शक्तियां प्राप्त नहीं थीं।  
2. प्राचार्य, रांची महिला महाविद्यालय से अवैध तरीके से

भुगतान किये गये आवास भत्ते के वसूली के लिए 06.04.2022 को कुलाधिपति कार्यालय द्वारा आदेश दिया गया था। उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया गया।  
3. रांची विश्वविद्यालय, रांची में 109 करोड़ रुपये की राशि की वित्तीय अनियमितता के संबंध में निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा 28.06.2021 को जांच प्रतिवेदन के साथ कार्रवाई के लिए राज्यपाल सचिवालय को प्रेषित किया गया था। 02.06.2022 को इस कार्यालय द्वारा तत्कालीन कुलपति, वित्तीय सलाहकार, वित्त पदाधिकारी एवं कुलसचिव के विरुद्ध आरोप पत्र गठित करने के

लिए निर्देशित किया गया था। उक्त विषयक संचिका कुलपति कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने की सूचना वर्तमान कुलपति द्वारा राज्यपाल सचिवालय को दी गयी है। विश्वविद्यालय की संचिका के नोट-शीट से यह स्पष्ट होता है कि यह संपूर्ण विषय कुलपति की पूर्ण जानकारी में था, किंतु कोई कार्रवाई नहीं की गयी, जबकि डॉ कामिनी कुमार कुलपति के प्रभार में थीं।  
4. डॉ गौरी जिलानो की सेवा नियुक्तिकरण के प्रस्ताव पर प्रतिकुलपति-सह-स्क्रॉनिंग समिति की अध्यक्ष के तौर पर दो माह में दो संपूर्ण विरोधाभासी तथ्य प्रेषित

किये गये, जिस कारण निर्णय लेने में दुविधा की स्थिति उत्पन्न हुई। इस संबंध में भी स्थिति स्पष्ट करने के लिए निर्देश दिया गया।  
5. 20.06.2022 को नये कुलपति की नियुक्ति की अधिसूचना जारी होने के पश्चात डॉ कामिनी कुमार के द्वारा तत्कालीन कार्यवाहक कुलपति के तौर पर स्वयं हस्ताक्षर करते हुए एक एमओयू विज्ञान प्रसार संस्थान के साथ किया गया। सामान्यतः विश्वविद्यालय के तरफ से यह कार्य कुलसचिव द्वारा किया जाता है, जो इस आशय में स्वतः कुलपति के तौर पर डॉ कामिनी कुमार के द्वारा किया गया।

41वां भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला- 2022

# झारखण्ड दिवस समारोह

## उद्योग विभाग झारखण्ड सरकार द्वारा

मुख्य अतिथि

# श्री हेमन्त सोरेन

माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड

की गरिमामयी उपस्थिति में

## आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं जोहार

दिनांक- 24 नवम्बर, 2022 | समय- संध्या 5 बजे  
स्थान- एम्फीथिएटर, प्रगति मैदान, नई दिल्ली

समारोह का सीधा प्रसारण [/jhg0vtv/](https://www.youtube.com/channel/UCjhg0vtv/)

P.R. 283233 (IPRD) 22-23 सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखण्ड सरकार







## कार्यक्रम : 13 करोड़ की लागत से बनेगा बिरसा मुंडा स्मारक सह हेलीपैड पार्क, मंत्री ने शिलान्यास कर कहा देश का सबसे विकसित राज्य बनेगा झारखंड



**विकास विरोधी लोग पंचायत चुनाव भी नहीं जीत सकते : मिथिलेश ठाकुर**

**आजाद सिपाही संवाददाता**

गढ़वा। शहर के कल्याणपुर स्थित हेलीपैड के समीप बिरसा मुंडा स्मारक पार्क सह हेलीपैड पार्क, विकास भवन एवं रिसोपेशन भवन का निर्माण किया जाएगा। बुधवार को गढ़वा विधायक झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने पूजा अर्चना कर, नारियल फोड़कर एवं शिलापट्ट का अनावरण कर व भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। 13 करोड़, 15 लाख, 50 हजार रुपये की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा।

मौके पर मंत्री श्री ठाकुर ने कहा कि शहरी जीवन में स्वस्थ जीवन शैली के लिए पार्क की

महत्वपूर्ण भूमिका है। पार्कों में ही शहरवासी शुद्ध हवा में सांस लेते हैं। जीवन की भाग्यी से दूर सुकून के पल पार्क में ही बिताते हैं। इस तरह के पार्क की गढ़वा में कमी थी, जो आज पूरा किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि उन्होंने पिछले वर्ष स्थापना दिवस के मौके पर ही पार्क बनवाने की घोषणा की थी। उन्होंने मुख्यमंत्री को जब बताया गया कि गढ़वा में कहीं भी भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा नहीं है, तब उन्हें घोर आश्चर्य हुआ। मुख्यमंत्री ने तत्काल बिरसा मुंडा स्मारक पार्क निर्माण की स्वीकृति प्रदान किया।

मंत्री ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में झारखंड सरकार काफी बेहतर कार्य कर रही है। यदि किसी भी जनप्रतिनिधि के पास इच्छाशक्ति हो तो विकास कार्य में कोई भी बाधा आड़े नहीं आ सकती है। मंत्री ने कहा कि

### एसडीओ ने शहर में संचालित अस्पतालों का किया निरीक्षण, जायसवाल क्लिनिक को किया सील



**बंशीधर नगर (आजाद सिपाही)।** अनुमंडल पदाधिकारी आलोक कुमार ने शहर में संचालित विभिन्न अस्पतालों के निरीक्षण किया। इस दौरान स्टेट बैंक के समीप स्थित

जायसवाल क्लिनिक को अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक के उपस्थिति में सील कर दिया। जायसवाल क्लिनिक में निरीक्षण के दौरान बिना चिकित्सक के उपस्थिति में मरीज का इलाज किया जा रहा था। जिसे देखकर एसडीओ भड़क गए। उन्होंने तत्काल अस्पताल को सील कर दिया। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर अस्पताल में नहीं थे। डॉक्टर की अनुपस्थिति में कंपाउंडर द्वारा भवनाथपुर थाना क्षेत्र के चौरासी गांव निवासी मकबूल अंसारी की पत्नी मैरून बीबी को स्लाइन चढ़ाया जा रहा था। उन्होंने इस मामले में कंपाउंडर से पूछताछ की। कंपाउंडर ने बताया कि दूरभाष पर डॉक्टर से बात कर स्लाइन चढ़ाया जा रहा है। इसके अलावे एसडीओ ने बंशीधर हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, उत्तम डायमोसिस सेंटर, गुलाब हॉस्पिटल सहित अन्य अस्पतालों का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीओ ने सभी अस्पतालों के व्यवस्था की जानकारी लेते हुए कागजात की जांच की। एसडीओ आलोक कुमार ने कहा कि अनुमंडल क्षेत्र के सभी अस्पतालों की जांच की जा रही है। जांच के दौरान जायसवाल क्लिनिक को सील किया गया है। कागजात की जांच के बाद अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जायसवाल क्लिनिक में बिना चिकित्सक के अस्पताल के कंपाउंडर द्वारा मरीजों को स्लाइन चढ़ाया जा रहा था, जो गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि अस्पताल के चिकित्सक आयुर्वेदिक चिकित्सक है। ऐसे में अस्पताल पूरी तरह अवैध है। उन्होंने कहा कि इलाजतर मरीज को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभियान के दौरान अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक सुचित्रा कुमारी, सहायक दीपेश राज तामांग, अशफाक अहमद और अनुमंडल कार्यालय के कर्मी उपेंद्र कुमार मौजूद थे।

## प्रदर्शन : झारखंड सरकार की नीतियों के खिलाफ हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया आक्रोश प्रदर्शन झामुमो सरकार ने झारखंड की जनता को लूटने का काम किया है : दिनेशानंद गोस्वामी

**झामुमो के मंत्री विधायक मोदी सरकार के काम का खुद का काम बताकर ताली बजाने में लगे रहते हैं : सांसद वीडी राम**

**आजाद सिपाही संवाददाता**

गढ़वा। हेमंत सरकार की नीतियों के विरोध में भाजपा जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश केशरी की अध्यक्षता में हजारों कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर जन आक्रोश प्रदर्शन कार्यक्रम किया। कार्यक्रम की शुरुआत रामसाहू के मैदान से की गयी जो मंडिआंव मोड़-रंका मोड़ होते हुए गढ़वा जिला समाहजणालय पहुंचा। जहां सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी ने कहा कि झामुमो सरकार ने झारखंड की जनता को लूटने का काम किया है। सरकार में बैठे गढ़वा विधायक सह मंत्री मिथिलेश ठाकुर गढ़वा सहित पूरे झारखंड में माफिया राज चला रहे हैं और मुख्यमंत्री भी मौनी बाबा



बनकर सब देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि झामुमो सरकार का पूरा कुनबा झारखंड को ऐसे लूटने में लगा है जैसे अब दुबारा इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। झारखंड की जनता झारखंड को लूटने में लगा है। उन्होंने कहा कि झारखंड में युवाओं को रोजगार और बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर झामुमो ने ठगने का काम किया है।

पलामू सांसद बीडी राम ने कहा कि झामुमो सरकार में लूट की पूरी छूट है। मुख्यमंत्री झारखंड को लूटने में मस्त हैं। उन्होंने कहा कि गढ़वा जिला सहित पूरे झारखंड में झामुमो सरकार ने विकास का कोई काम नहीं किया। झामुमो सरकार पूरी तरह से माफिया के चंगुल में फंस चुकी है। झामुमो के मंत्री विधायक मोदी

## सौ से अधिक लोगों ने थामा झामुमो का दामन, मंत्री ने किया स्वागत

**आजाद सिपाही संवाददाता**

गढ़वा। जिले के रंका प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से करीब एक सौ से अधिक महिला-पुरुषों ने अन्य राजनीतिक दलों को छोड़कर झामुमो का दामन थाम लिया। लोगों ने भाजपा, बसपा एवं राजद को छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण की। बुधवार को गढ़वा विधायक झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने गढ़वा स्थित अपने आवास पर सभी को माला पहना



कर स्वागत करते हुए पार्टी में शामिल कराया। मौके पर मंत्री श्री ठाकुर ने कहा कि झारखंड सरकार पूरे

राज्य में अंतिम पंक्ति के लोगों तक विकास कार्य पहुंचा रही है। राज्य में सभी वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर विकास योजनाएं

चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यों से प्रभावित होकर गढ़वा सहित पूरे राज्य में लोग विभिन्न पार्टियों को छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो रहे हैं। झारखंड सरकार सभी वर्ग के लोगों को पूरा हक एवं अधिकार दे रही है। मौके पर मुख्य रूप से झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे, जिलाध्यक्ष तनवीर आलम, सचिव मनोज ठाकुर, नवीन तिवारी, आशुतोष पांडेय, अनिता दत्त सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।

आज विकास विरोधी लोग हर कदम पर विकास कार्यों का विरोध कर रहे हैं। परंतु विकास विरोधी लोग विधानसभा तो क्या पंचायत चुनाव भी नहीं जीत सकते हैं। इतना सुनिश्चित है कि अब ऐसे विकास विरोधी आजीवन विधानसभा का मुंह नहीं देख पायेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा झारखंड की साढ़े तीन करोड़ जनता का अभिमान कर रही है। इसे हमेशा भाजपा के लोग उखाड़ फेंकने की बात करते हैं। यह सरकार जनता की चुनी हुई जन सरोकार की सरकार है, कोई

गाजर मूली नहीं है। जनता सब जान चुकी है। आगामी चुनाव में भाजपा विपक्ष में भी बैठने के लायक नहीं रहेगी। गढ़वा की जनता ने जिन-10 वर्षों तक मौका दिया। उनका एक भी कार्य आज देखने लायक नहीं है। मंत्री ने कहा कि निर्माण के साथ ही नीलांबर पीताम्बर पार्क एवं घंटाघर की बेहतर देखरेख एवं रखरखाव की जिम्मेवारी ग्रासिम इंस्टीट्यूट रेहला को दे दी गई है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनायी जाती है। लोग उनके नाम

पर राजनीति करते हैं, परंतु आज तक गढ़वा में उनकी एक भी प्रतिमा नहीं थी। मंत्री ने कहा कि पार्क के निर्माण का समय एक साल निर्धारित है, परंतु आगामी छह माह के अंदर इसका निर्माण कार्य पूर्ण कर जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। मौके पर डीडीसी राजेश राय, जुडको के प्रोजेक्ट चेयरमैन अनुराग कुमार, जपि अध्यक्ष शांति देवी, उपाध्यक्ष सत्यनारायण यादव, प्रमुख विमला देवी, मुखिया अशोक चंद्रवंशी आदि ने विचार व्यक्त किया।

मौके पर मुख्य रूप से एसडीओ राज महेश्वरम, एसडीपीओ अवध कुमार यादव, नप अध्यक्ष पंकी केशरी, झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे, जिलाध्यक्ष तनवीर आलम, सचिव मनोज ठाकुर, विधायक प्रतिनिधि कंचन साहू, जितेंद्र सिंह, अनिता दत्त, परेश तिवारी, मुन्ना सिंह, आशुतोष पांडेय, नवीन तिवारी, दिव्य प्रकाश केशरी, मदनो खान, झामुमो महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष अंजली गुप्ता, रेखा चौबे, दीपमाला आदि सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे।

## अजा, अजजा, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

**उपायुक्त ने प्रत्येक प्रधानाध्यापक को एक सप्ताह में लगभग 40 प्रतिशत छात्रों का निबंधन कल्याण पोर्टल पर निबंधित कराना कराने का दिया निर्देश**

**आजाद सिपाही संवाददाता**

गढ़वा। उपायुक्त रमेश घोषल की अध्यक्षता में समाहजणालय स्थित सभाकक्ष में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याण शाखा अंतर्गत प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य रूप से जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक तथा प्रखंड स्तर से सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, सभी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड से प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक उपस्थित थे। सर्वप्रथम जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के नया नियमावली के बारे में बताया गया जिसके तहत



अब कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को 15 सौ रुपये, कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को 25 सौ रुपये एवं कक्षा 9 से 10 को 45 सौ रुपये छात्रवृत्ति की राशि भुगतान की जाएगी। कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए आय की कोई सीमा नहीं होगी। परंतु कक्षा 9 एवं 10 के लिए (अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग अंतर्गत) आय की अधिकतम सीमा ढाई लाख रुपये होगी। बैंक से जुड़ी समस्या के बारे में जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि यदि किसी छात्र के पास अपना खुद का बैंक खाता नहीं है तो कल्याण पोर्टल पर ऐसी व्यवस्था की गई है कि छात्र अपने माता या पिता किसी एक का बैंक खाता देकर छात्रवृत्ति हेतु

निबंधन करा सकते हैं। ई-कल्याण पोर्टल से संबंधित ऑनलाइन प्रक्रिया से भी सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, सभी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड के कार्यक्रम प्रबंधक को अवगत कराया गया। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को उपायुक्त श्री घोषल द्वारा निर्देश दिया गया कि प्रत्येक प्रधानाध्यापक के द्वारा एक सप्ताह में लगभग 40% छात्रों का निबंधन कल्याण पोर्टल पर निबंधित कराना सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद अगले एक सप्ताह में 80% तथा एक महीने के अंदर शत-प्रतिशत योग्य छात्र-छात्राओं का निबंधन करना सुनिश्चित करेंगे।

### रंका प्रखंड में पीएम आवासों में कराया गया गृहप्रवेश

रंका (आजाद सिपाही)। रंका बीडीओ देवानंद राम ने 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक गृह प्रवेश पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अंबेडकर आवास योजना के लाभार्थियों को अपने अपने पंचायतों में गृह प्रवेश कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि संबंधित पंचायत के मुखिया एवं पंचायत सचिव आवास लाभार्थियों को जल्द से जल्द आवास पूर्ण कराने हेतु प्रेरित करें। साथ ही साथ वैसे लाभार्थी जो आवास को सुंदर व ससमय पूरा करते हैं उन्हें पुरस्कृत भी करने का निर्देश दिया है। बीडीओ के द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में कंचनपुर पंचायत के मुखिया प्रतिमा देवी एवं मुखिया व प्रतिनिधि चंद्रशेखर कुमार के द्वारा गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जिसमें उनके द्वारा कंचनपुर गांव के जीवनाथ रजक, धर्मेन्द्र कुमार यादव, देवनाथराय यादव, ओष्या ठाकुर, श्रवण ठाकुर आदि का गृह प्रवेश कराया गया। इस अवसर पर कंचनपुर पंचायत के स्वयंसेवक नंदू राम, उप मुखिया चंद्रशेखर तिवारी, वार्ड सदस्य अजय चंद्रवंशी, धर्मेन्द्र कुमार यादव तथा वीरेंद्र कुमार चंद्रवंशी, राहुल कुमार रवि, विजय राम उर्फ ताशवाले मुख्य रूप से उपस्थित थे।

## समाजसेवी दौलत सोनी ने बजरंगबली मंदिर में कराया सुंदरीकरण का कार्य



**युवा समाजसेवी की ओर से गढ़वा शहरी क्षेत्र में लगातार किये जा रहे हैं विकास कार्य**

**आजाद सिपाही संवाददाता**

गढ़वा। युवा समाजसेवी दौलत सोनी के द्वारा बजरंगबली मंदिर का किया गया सुंदरीकरण। उनके द्वारा गढ़वा शहरी क्षेत्र में लगातार विकास का कार्य किया जा रहा है। चाहे गर्मी के दिनों में लोगों के घरों तक टैकर के माध्यम से स्वच्छ जल पहुंचना हो या छठ घाट के पास पीपा पुल की मरम्मत या छठ घाट की जेसीवी के माध्यम से सफाई, मेन रोड में उड़ते धूल से निजात दिलाने के लिए सड़कों पर टैकर से पानी का छिड़काव या घर घर आम की लकड़ी तथा फल हर

असहाय की मदद करना हो या हर जरूरतमंद की सेवा चाहे रक्तदान हो या इलाज आधी रात को भी ये हर किसी की मदद के लिए उपास्थित रहते हैं। विकास की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए गांधी नगर रेलवे स्टेशन के बगल में अवस्थित जर्जर बजरंग बली के मंदिर का जीर्णोद्धार कर मंदिर परिसर में शिवलिंग की स्थापना करते हुए शिव चर्चा व भंडारा का आयोजन के साथ ही साथ पाठस मंडली के द्वारा सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इनकी जितनी सराहना की जाए कम है। विकास की इस कड़ी में अगला नाम जुड़ने जा रहा है तेनार घाट पर पीपा पुल का निर्माण, जिससे कि तेनार के ग्रामीण बहुत ही कम दूरी तय कर गढ़वा आ सकते हैं।

### आयुष मेला को लेकर बीडीओ ने की बैठक

बंशीधर नगर (आजाद सिपाही)। प्रखंड कार्यालय के सभागार में बुधवार को प्रखंड में आयोजित होने वाले दो दिवसीय आयुष मेला के सफल संचालन को लेकर बीडीओ श्रवण राम ने बैठक की। बैठक में 26 व 27 नवंबर को आयुष मेला ट्रॉफा सेंटर में आयोजित करने का निर्णय लिया गया। आयुष मेला में बीपी, सुगर, कैसर नियंत्रण जागरूकता, सामान्य चिकित्सा, त्वचा जांच, मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य सहित अन्य पुरानी बीमारियों का इलाज किया जायेगा। बैठक में जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी डॉ कृष्ण कुमार, डॉ अखिलेश कुमार, डॉ रंजिता अजम सिद्धीकी, प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष शैलेश कुमार चौबे, सीडीपीओ रीना साहू, मुखिया मनोज ठाकुर, सनिधा सोनी, फिरदौस अंसारी, कुमारी रेखा सहित अन्य उपस्थित थे।

### OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER MINOR IRRIGATION DIVISION KODERMA

#### Two Envelope System E-RPROCUREMENT Notice

Tender Reference No- WRD/MID/KODERMA/F2-20/2022-23 Date-23-11-2022		
Sl. No.	Name of Work	Renovation of Gadgi Aahar, Village- Gadgi, Block- Jainagar.
1	Estimated Cost (BOQ) (Rs)	82.920 Lakh
2	Cost of Tender fee	10,000.00 (Ten Thousand)
3	EMD	1, 66,000.00 (One Lakh Sixty Six Thousand) Only.
4	Tender Reference No	WRD/MID/KODERMA/F2-20/2022-23
5	Completion Period for Construction	11 Months
6	Mode of submission of Tender	Online through
7	Publishing on website	Date-09-12-2022 - 2.00. P.M
8	Period of Downloading of Bidding Documents	Start Date:- 09-12-2022 Time: 2.00 PM End Date:- 15-12-2022 Time: 5.00 PM
9	Bids online submission	Start Date:- 09-12-2022 Time: 2.00 PM End Date:- 15-12-2022 Time: 5.00 PM
10	Submission of BID Security & Hard Copy	Date:- 16-12-2022 up to 3.00 PM
11	Technical Bid Opening Date	Date:- 17-12-2022 at 2.00 PM
12	Officer inviting Bids	Executive Engineer Minor Irrigation Division, Koderma.
13	Office received Hard Copy and Bid Security	1. E.E M.I Division Koderma. 2. S.E M.I Circle Hazaribagh. 3. E.E M.I Design Division, Ranchi.

**NOTE:-** The Tender fee, Earnest Money Deposit (EMD) and Affidavit (Attached Performa) and Bank Certificate for Credit Facility must be submitted up to 16-12-2022 by 3.00 PM. If Tender fee, EMD, Affidavit and Bank certificate for Credit Facility are not received before mention date and time tender shall not be accepted. **Place to receiving Tender fee, EMD, Affidavit and Bank certificate for Credit Facility** Executive Engineer Office, M.I. Division, Koderma / S.E. Office M.I. Circle Hazaribagh / Executive Engineer Office, M.I. Design Division, Ranchi. **Executive Engineer, Minor Irrigation Division, Koderma.** PR 283170 (Minor Irrigation) 22-23 (D)

### झारखण्ड सरकार श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग अवर प्रादेशिक नियोजनालय, हजारीबाग

**मर्ती कैम्प, दिनांक - 25.11.2022**  
**सूचना**  
अवर प्रादेशिक नियोजनालय-सह- मॉडल कॅरियर सेंटर हजारीबाग द्वारा दिनांक - 25.11.2022 को कार्यालय परिसर में 10:00 बजे पूर्वाह्न से 4:00 बजे अपराह्न तक Assist Services PVT, LTD Bokaro City Jharkhand द्वारा Marketing Executive, Mechanics, Marketing Manager & office Staff - पद हेतु एक दिवसीय मर्ती कैम्प का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विवरण निम्न है :-  
**WORK PLACE : HAZARIBAG**

S. No	Name of the post	Number vacancies	Qualification		Age(yrs)	Salary	Experience
			Minimum	Maximum			
1	Marketing Executive	80	12 <sup>th</sup>	Graduation	23 upto 40	14,000 pm	Market Knowledge
2	Mechanics	06	ITI	-	22-30	12,000 pm	Filter Electrical Mechanical
3	Marketing Manager	02	Graduation	PG	30 or more	13,000 pm	1 year experience in office
4	Office Staff	02 (Female)	12 <sup>th</sup>	-	-	-	-

योग्य एवं इच्छुक आवेदक (उम्मीदवार) जो पूर्व से निबंधित नहीं है वे अपने निकटतम नियोजनालय में अथवा [www.rojgar.Jharkhand.gov.in](http://www.rojgar.Jharkhand.gov.in) पर अपना निबंधन कराते हुए उपरोक्त उल्लेखित मर्ती कैम्प में नियोजक / नियोजक के प्रतिनिधि के समक्ष अपने सभी मूल प्रमाण-पत्रों एवं उसकी छाया प्रतियों तथा वायोडाटा दो प्रतियों में, दो पासपोर्ट साईज का फोटो के साथ साक्षात्कार हेतु उपस्थित हो सकते हैं। जो उम्मीदवार पूर्व से निबंधित हैं उन्हें पुनः निबंधन करवाने की आवश्यकता नहीं है। चूँकि रिक्ति निजी क्षेत्र से संबंधित है, अतः पूर्व चयन की प्रक्रिया में नियोजनालय का किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं रहेगा। कोविड - 19 हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों/SOP का दृढ़ता पूर्वक अनुपालन किया जाना आवश्यक है। अतः समाजिक दूरी का पालन, फेसमास्क सैनिटाइजर एवं ग्लब्स इत्यादि का उपयोग करेंगे। इस निमित्त किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा।

नियोजन पदाधिकारी अवर प्रादेशिक नियोजनालय हजारीबाग  
PR 283227 Labour Employment and Training (22-23)\_D





## जलमीनार का उद्घाटन के बाद भी मुहल्ले के लोग पानी के सुविधाओं से हैं महरूम : सैयदा खातून



गुमला (आजाद सिपाही)। मिशन बदलाव महिला जिला सचिव सैयदा खातून ने कुरैशी मुहल्ला एवं आजाद बस्ती एवं बाजार टांड का दौरा किया। सैयदा खातून ने बताया कि पिछले महीने 22 तारीख को जलमीनार बना के प्रशासन ने मुहल्लों वालों को हैडओवर किया। उसके बाद भी अभी तक जलमीनार शुरू नहीं हुआ। सैयदा ने बताया कि अभी भी लगभग 90 परिवार जलमीनार का फायदा उठा सकते हैं एवं हाट बाजार भी यहीं पर लगता है, कई लोगों को इसका फायदा मिल सकता है, लेकिन प्रशासनिक खानापूर्ति करके योजनाओं का धरातल में दिखा तो दिया जाता है लेकिन कोई उपयोगिता नहीं है। सैयदा ने कहा कि आमजनों की परेशानी को देखते हुए प्रशासन जलमीनार को शुरू करे। जिससे कि आमलोगों को इसका फायदा मिल सके। मिशन बदलाव की सैयदा ने कहा कि अभी पूरे वार्डों में पानी की किल्लत से पूरी जनता परेशान है एवं इस मामले पर प्रशासन को त्वरित कदम उठाने की जरूरत है। सैयदा खातून मुहल्लों में घूम घूम कर लोगों की समस्याओं से भी अवगत हुईं। जिसमें मेहरूम निशा, आफरीन परवीन, खैरूम निशा, तबरेज कुरैशी, फैजुल अंसारी, नाजिया परवीन, रेहान कुरैशी, खुशीद आलम, पप्पू अंसारी इत्यादि लोग मौजूद थे।

सकूल के बगल की जलमीनार हुई खराब, पानी की बोटल लेकर जाते हैं बच्चे स्कूल : नारायण भगत



गुमला (आजाद सिपाही)। मिशन बदलाव के नारायण भगत ने बताया कि घाघरा प्रखंड के सेहल पंचायत गुरियादिह गांव की समस्या वहां पानी की काफी दिक्कत है। वहां पर एकमात्र जलमीनार खराब है और स्कूल के सभी बच्चे जब स्कूल आते हैं तो वही जलमीनार का पानी पीते थे, लेकिन एक वर्ष से जलमीनार खराब पड़ी हुई है और सभी बच्चे पीने का पानी को लेकर परेशान हैं और स्कूल जाने के क्रम में बोटल में पानी लेकर स्कूल जाते हैं, जबकि पंचायत सेवक एवं मुखिया को भी इन सभी मामलों को लेकर अवगत कराया गया, लेकिन उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। लगातार मुखिया इन सभी मामलों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। विधायक मद से करायी गयी डीप बोरिंग भी असफल हो गयी है, अभी वह चालू नहीं है। अभी एक साल लगभग हो गया है लेकिन अभी तक जलमीनार नहीं बनी। नारायण भगत ने कहा कि गांव में बच्चों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन जलमीनार को तुरंत ठीक कराये। जिससे कि आम लोगों एवं बच्चों को पानी की समस्याओं से निजात मिल सके।

घाघरा प्रखंड कांग्रेस कमेटी ने भारत जोड़ो पदयात्रा निकाली



घाघरा (आजाद सिपाही)। घाघरा प्रखंड कांग्रेस कमेटी द्वारा कांग्रेस द्वारा चल रही नफरत तोड़ो भारत जोड़ो को लेकर बुधवार को पदयात्रा

घाघरा मुख्यालय में निकाली गयी। पदयात्रा को नेतृत्व प्रखंड अध्यक्ष अरुण कुमार पांडे ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत घाघरा प्रखंड के नवडीहा टाना स्कूल में स्थित गांधीजी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर की गयी। जहां से पदयात्रा करते हुए कांग्रेसी घाघरा ब्लॉक चौक बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर चांदनी चौक पहुंचे शहीद देवनारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जहां पदयात्रा सभा में तब्दील हो गयी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता शिव कुमार भगत टुनटुन ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आयी है तब से लेकर आठ सालों में देश में अराजकता फैली, नफरत को लेकर आर्थिक मंदी, संविधान को बचाने को लेकर और लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी आगे आयी है। हमारे नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा कर नफरत छोड़ो भारत जोड़ो को लेकर अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में आज पदयात्रा निकाली गयी है। वहीं महिला प्रदेश उपाध्यक्ष बाबी भगत ने देश में फैली अराजकता और नफरत फैलाने वाली भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों को आवाज बुलंद करने की बात कही। वहीं कार्यक्रम के प्रभारी संयोजक चैतु उरांव, युवा जिलाध्यक्ष आजाद अंसारी, बिशनपुर विधानसभा उपाध्यक्ष आदित्य भगत, अरुण कुमार पांडे ने भी संबोधन में केंद्र के भाजपा सरकार पर जमकर बरसे और लोगों को एकजुट होने की अपील की। इस मौके पर उपस्थित लोगों में पूर्व प्रदेश प्रवक्ता शिव कुमार भगत, महिला प्रदेश उपाध्यक्ष बाबी भगत, पदयात्रा के संयोजक चैतु उरांव, बिशनपुर विधानसभा उपाध्यक्ष आदित्य भगत, प्रखंड अध्यक्ष अरुण कुमार पांडे, दिलबहार अंसारी, फल्लव कुजर, शहजाद खान, अशोक उरांव, अगस्टिन महेश कुजर, विनीता उराव, सरोजिनी किरण भगत सहित कई कांग्रेसी शामिल थे।

## कामडारा बीडीओ व बीपीओ की मिलीभगत से प्रखंड में मची है लूट

सामाजिक कार्यकर्ता रोहित कुमार नाग के गुमला के डीडीसी व डीसी को दिये गये आवदन से हुआ खुलासा



कामडारा। कामडारा की बीडीओ अमृता प्रियंका एक्का और प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी रेणुका किंडो पर अनियमितता का आरोप लगाया गया। उक्त पदाधिकारियों द्वारा प्रखंड क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों एवं सरकारी लाभ प्राप्त कर रहे लाभुकों को मनरेगा योजना के तहत गलत ढंग से योजना देने का आरोप है। इस संबंध में कामडारा प्रखंड के एक सामाजिक कार्यकर्ता रोहित कुमार नाग ने गुमला के उप विकास आयुक्त व उपायुक्त कुमला को एक आवेदन सौंपकर निष्पक्ष जांच व कार्रवाई

## बैठक : गुमला में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 28 नवंबर को पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता यात्रा को सफल बनाने में जुटें : रमेश चीनी

नगर व सदर प्रखंड कांग्रेस कमेटी की संयुक्त बैठक में भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने का लिया गया निर्णय

आजाद सिपाही संवाददाता

गुमला। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो कार्यक्रम को लेकर एक बैठक बुधवार को स्थानीय परिसदन में हुई। बैठक की अगुवाई संयुक्त रूप से गुमला नगर अध्यक्ष मोहम्मद खालिद एवं गुमला प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद सरवर ने की।

जिला 20 सूत्री सदस्य रमेश कुमार चीनी ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में रमेश कुमार चीनी ने कहा कि जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी, मंच मोर्चा एवं



कार्यकर्ता इस यात्रा को सफल बनाने के लिए जी जान से लग जायें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ने का प्रयास करें तथा लोगों को इस यात्रा के उद्देश्य से अवगत करायें।

नगर अध्यक्ष मोहम्मद खालिद ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा लोगों को आमस में प्यार एवं भाईचारा से जुड़ने का बहुत बड़ा माध्यम है। इस यात्रा से पार्टी के

विचारों को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने का प्रयास करें।

प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद सरवर ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा 28 नवंबर 2022 को 10:00 बजे से रखी गई है। इस कार्यक्रम के तहत यात्रा डीएवी स्कूल लोहरदगा रोड गुमला से पुलिस लाइन चंदौली सोसा मोड़ होते हुए लोहरदगा रोड पहुंचेगी। जिसके बाद थाना चौक से थाना रोड होते हुए टावर चौक,

## भ्रष्टाचार, महंगाई व बेरोजगारी जनविरोधी सरकार की देन है : विजय सिंह

झारखंड नवनिर्माण दल ने किया कैडर कन्वेंशन का आयोजन

आजाद सिपाही संवाददाता

गुमला। झारखंड नवनिर्माण दल का कैडर कन्वेंशन गुमला स्थित परिसदन की मीटिंग हॉल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता दल की वरिष्ठ महिला नेत्री पुष्पा उरांव ने की। कन्वेंशन में मुख्य रूप से उपस्थित झारखंड नवनिर्माण दल के केंद्रीय संयोजक विजय सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार, महंगाई व बेरोजगारी जनविरोधी सरकार का देन है। केंद्र व राज्य सरकार के पास ऐसी समस्या से आम जनता को निजात दिलाने के लिए कोई नीति नहीं है, जिसके खिलाफ आंदोलन शुरू करने की बात श्री सिंह ने बतायी। उन्होंने जिले में जागो अभियान को तेजी से बढ़ाते हुए दल के केंद्रीय समिति द्वारा मजदूर किसानों की समस्याओं को लेकर रांची



राजभवन के समक्ष 13 दिसंबर 2022 को आयोजित धरना कार्यक्रम एवं 28 फरवरी 2023 को रांची में विशाल महापंचायत की तैयारी में अभी से जुटने की भी अपील कार्यकर्ताओं से की है। महिला नेत्री पुष्पा उरांव ने कहा कि राज्य में महिला उत्पीड़न की घटना बढ़ी है जिसके खिलाफ 4 दिसंबर 2022 से जागो अभियान के तहत गुमला में आंदोलन शुरू करने की बात कही। कन्वेंशन को प्रकाश उरांव, आदित्य सिंह, अजीत विश्वकर्मा, सरिता देवी सहित कई नेताओं ने संबोधित किया।

कन्वेंशन में भ्रष्टाचार के

खिलाफ व जिले की जन समस्याओं को लेकर 28 नवंबर 2022 को जिला मुख्यालय में चेतावनी कार्यक्रम करने, गुमला को रेल लाइन से जोड़ने के लिए हस्ताक्षर अभियान को आगे बढ़ाते हुए रेल लाइन व गुमला-लोहरदगा के सीमांत पर एल्युमिनियम कारखाना निर्माण की मांग को लेकर भात सिंह के शहादत दिवस 23 मार्च 2023 को रांची में गुमला जिला समिति द्वारा विशाल धरना कार्यक्रम करने, राजभवन के समक्ष 13 दिसंबर का धरना प्रदर्शन में गुमला जिला से एक हजार मजदूर- किसानों को रांची ले जाने तथा 28 फरवरी

## सरस्वती शिशु मंदिर डुमरी में धूमधाम से मनाया गया जनजाति गौरव दिवस

डुमरी (आजाद सिपाही)। सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय डुमरी में धूमधाम के साथ जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सशिविमं महुआडांड के प्रधानाचार्य सह संकुल प्रभारी चंद्र कुमार बेसरा एवं विशिष्ट अतिथि सशिमं चैनपुर के प्रधानाचार्य बाबूलाल कुमार शामिल हुए। सर्वप्रथम भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं अतिथियों को विद्यालय प्रबंध समिति की ओर से अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही विद्यालय के बच्चों के द्वारा स्वागत गान प्रस्तुत किए गए। वहीं विगत सप्ताह लोहरदगा में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा आयोजित प्रांत स्तरीय वनवासी खो खो प्रतियोगिता में चयनित कुल आठ भैया

प्रांत स्तरीय वनवासी खो खो प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित



बहनों को विद्यालय परिवार की ओर से पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जिनमें प्रतिभा कुमारी, रिमझिम कुमारी, मनीषा कुमारी, शालिनी कुमारी, रोमिसर लोहरा, रायल कवर, राम भगत एवं लक्ष्मण भगत के नाम शामिल हैं।

वहीं मुख्य अतिथि ने जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा की जीवनी पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालते हुए खो खो प्रतियोगिता में प्रांत स्तरीय खेल में बेहतर प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान से जीत हासिल करने हेतु बधाई दी है। वहीं विद्यार्थियों से कहा कि अगला खेल उत्तर प्रदेश में होगा। इसके लिए खिलाड़ियों से मेहनत कर अच्छे तरह तैयारी करने की अपील की। साथ ही विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष व सचिव सहित अन्यो ने अपने विचार प्रकट किये। मौके पर अध्यक्ष राजेश केशरी, सचिव उदय साहू, संरक्षक सञ्जालाल साहू, अनुपूर्णा देवी, प्रधानाचार्य दुलार इंदवार, एजरस टोप्पो, आयुष कुमार, सोमन कुमारी, रानी कुमारी, प्रेमा कुजूर, रोसालिया टोप्पो, रीना एक्का सहित विद्यालय के सैकड़ों भाईया व बहन उपस्थित थे।

## अवैध बालू भंडारण को लेकर सीओ ने प्राथमिकी दर्ज करायी

सिसई (आजाद सिपाही)। अवैध

बालू भंडारण को लेकर सीओ अरुणिणा एक्का ने बुधवार को अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध खनिज अधिनियम के तहत सुसंगत धारा पर प्राथमिकी दर्ज करायी। दर्ज केस में कहा गया है कि बीते मंगलवार को थाना प्रभारी व पुलिस बल के साथ असरो तेतरतौली में बालू भंडारण का निरीक्षण किया गया। जहां एक खेत में करीब छह हजार घनफुट बालू भंडारण पाया गया। जांच पड़ताल में अज्ञात व्यक्ति द्वारा बालू भंडारण किये जाने की सूचना प्राप्त हुई। इस क्षेत्र में बालू भंडारण से संबंधित कोई अनुज्ञापति की स्वीकृति नहीं दी गई है। जिससे प्रतीत होता है कि अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अवैध रूप से नदी से उत्खनन कर भंडारण कर विक्री किया जाता है।

## महत्वपूर्ण न्यूज

### प्रधानाध्यापको की विभिन्न गतिविधियों पर समीक्षा सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन



भरनो (आजाद सिपाही)। कन्या मध्य विद्यालय, भरनो के सभागार में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी की अध्यक्षता में प्रखंडधीन सभी सरकारी/निजी विद्यालय के प्रधानाध्यपकों की विभिन्न गतिविधियों पर समीक्षा सह उन्मुखीकरण आयोजित किया गया। जिसमें निम्न बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा-परिचर्चा कर प्रधानाध्यपकों को निर्देश दिया गया। युवाइस+ पर विद्यालय के सभी गतिविधियों को एंटी करना अनिवार्य है साथ ही साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (दिव्यांग) बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए प्रथमिकता दें। मेधा छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन पंजीयन करना अनिवार्य है। विद्यालय विकास मद से रंग रोगन कार्यक्रम करना अनिवार्य। विद्यालय में हाइट माप स्केल दीवाल में बनाना जरूरी है और वेट मशीन लेना अनिवार्य है। मर्ज विद्यालयों में कार्यरत रसोइया सह सहायिका/संयोगिका के संदर्भ में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई और कई दिशा निर्देश दिए गए। प्रशिक्षण कार्यक्रम उपस्थित बीआरपी समीप एजाज, सुधीर कुमार साहू, सीआरपी विजय कुमार, भूपण केशरी, शशि भूपण, नूर इकराम, पूनम कुमारी, साहीन परवीन, रिसोर्स शिक्षक, वीरेंद्र कुमार रंजीत मढतो, मुकूल टेटे, अर्जुन केशरी, और प्रखंड के समस्त विद्यालय के प्रधानाध्यक उपस्थित थे।

### विकास भारती ने किया तीन दिवसीय बिरसा क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन



बिशनपुर (आजाद सिपाही)। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर विकास भारती बिशनपुर द्वारा तीन दिवसीय बिरसा क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन बुधवार को एसएस हाई स्कूल के स्टेडियम में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विकास भारती सचिव पद्मश्री अशोक भगत के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान भगवान बिरसा मुंडा अमर रहें जय जवान जय किसान के नारों से पूरा स्टेडियम गुंज उठा। इस प्रतियोगिता में प्रखंड क्षेत्र के 17 विद्यालय के बच्चों ने भाग लिया। मौके पर कार्यक्रम का उद्घाटन उपरांत अशोक भगत ने अपने संबोधन में कहा कि इस प्रकार के खेलों का आयोजन करने से खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। साथ ही प्रतिस्पर्धा की भावना भी जागृत होती है और अच्छा से अच्छा खेलने की प्रेरणा भी मिलती है। उन्होंने प्रतिभागियों को अच्छा खेलकर विजयी होने की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के प्रथम दिन बालक-बालिका, किशोर वर्ग एवं बाल वर्ग के लिए 100 मीटर से लेकर 400 मीटर दौड़ का आयोजन किया। साथ ही साथ ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक, भाला फेंक, पूरन सिंह, प्रशन साहू, बेनेदिक तिर्की, पुष्पा उरांव, सरिता देवी, कुसमा मिंज, मालती देवी सहित दल से जुड़े विभिन्न मंच मोर्चा के कई पदाधिकारी उपस्थित थे।

### प्रखंड कार्यालय परिसर में ग्रामीणों को गव्य विकास के लाभ पहुंचाने को लेकर की गयी बैठक



घाघरा (आजाद सिपाही)। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग जिला गव्य विकास गुमला द्वारा मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अंतर्गत गव्य विकास के लाभ को लेकर बुधवार को प्रखंड कार्यालय परिसर घाघरा में बैठक की। बैठक में जिला गव्य तकनीकी पदाधिकारी प्रमोद कुमार ने बैठक में उपस्थित मुखिया व पंचायत सचिव को जानकारी देते हुए कहा कि जो भी लाभुक गाय पालन, बकरी पालन, सूअर पालन करना चाहते हैं ग्राम सभा में नाम चढ़ायें। सरकार द्वारा 90% तक अनुदान दी जा रही है। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी विष्णु देव कच्छप ने कहा कि जनप्रतिनिधि और पंचायत के कर्मी आपस में समन्वय बनाकर जैसे लाभुक जो इसका लाभ देना चाहते हैं उनका नाम सभा में जोड़ें और उन्हें लाभ दिलाने के लिए कार्य करें। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अंतर्गत विकास कार्यक्रम के निमित्त दुधारू गाय पालन, सुकरा पालन, बकरी पालन सहित अन्य कई योजनाओं से लोगों को लाभान्वित करने की पहल की जा रही है। आप उसका समुचित लाभ उठावें। मौके पर जिला अकाउंटेंट अकाश कुमार गुप्ता सहित कई पंचायत के मुखिया और पंचायत सचिव व कर्मी उपस्थित थे।

### बीडीओ ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के प्राचार्य को प्रशस्ति पत्र सौंपा

बसिया (आजाद सिपाही)। झारखंड राज्य स्थापना दिवस-2022 के अवसर पर गुमला उपायुक्त सुशांत गौरव द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, बसिया के प्राचार्य संजय कुमार सिंह को सम्मानित किया गया था। 15 नवम्बर को गुमला से बाहर होने के कारण प्राचार्य श्री सिंह को यह सम्मान पत्र प्राप्त नहीं हो सका था। बुधवार को बीडीओ रविंद्र कुमार गुप्ता ने स्वयं विद्यालय में आकर यह प्रशस्ति पत्र प्राचार्य श्री सिंह को प्रदान किया। वहीं विद्यालय के खेल शिक्षक शुभम कुमार सिंह को भी 'खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य' हेतु उपायुक्त, गुमला द्वारा सम्मानित किया गया है। शारीरिक अस्वस्थता के कारण खेल शिक्षक के अवकाश में होने के कारण प्रखंड विकास पदाधिकारी रविन्द्र कुमार गुप्ता ने उनका प्रशस्ति पत्र भी प्राचार्य संजय कुमार सिंह को सौंपा। विद्यालय परिवार में इस उपलब्धि पर हर्ष का माहौल है। प्राचार्य श्री सिंह ने इस संदर्भ में कहा कि यह उपलब्धि के उपलब्ध उनकी नहीं बल्कि विद्यालय के सभी शिक्षकों व कर्मचारियों की उपलब्धि है क्योंकि सबके साप्ताहिक प्रयास से ही कोई सफलता मिलती है।







मप्र की कांग्रेस नेता ने खटखटाया अदालत का दरवाजा

# आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर

**आजाद सिपाही संवाददाता**  
**भोपाल।** सोमवार को एहर कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया था। अब उस निर्णय को लेकर मप्र के एक कांग्रेस नेता ने सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की एक नेता ने इडब्ल्यूएस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने इडब्ल्यूएस मुद्दों पर केंद्र के फैसले को बरकरार रखने के फैसले की खिलाफत की है। बता दें कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मिलने वाले एहर कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम फैसला सुनाया था। पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने



3:2 के बहुमत से संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा है, जो शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10% इडब्ल्यूएस आरक्षण प्रदान करता है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस जेबी पारदीवाला ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सहमति

**कांग्रेस नेता उदित राज ने भी किया था विरोध**  
फैसला आने के बाद कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा था कि वे इडब्ल्यूएस आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की उच्च जाति समर्थक मानसिकता का विरोध कर रहे हैं। जब अजा-जजा को आरक्षण की बात आती है तो वह इंदिरा साहनी मामले की दुहाई देकर अजा-जजा-ओबीसी को 50 फीसदी आरक्षण की सीमा का हवाला दिया जाता है। आज संविधान का हवाला देकर कहा जा रहा है कि नहीं, आरक्षण की कोई सीमा नहीं है।

जाहिर की थी। अब इस निर्णय पर समीक्षा याचिका लगायी गई है। मध्य प्रदेश की कांग्रेस नेता डॉ. जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर की, जिसमें 103वें संशोधन इडब्ल्यूएस आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया था।

# पूर्व तट रेलवे ने केवल 16 घंटों में क्षतिग्रस्त रेलवे ट्रैक के साथ अन्य बुनियादी ढांचे का पुनः कार्यक्षम कर दिया

**आजाद सिपाही संवाददाता**  
**भुवनेश्वर।** कोरई में प्रभावित रेल लाइन, जो सोमवार को सुबह मालगाड़ी के पटरी से उतरने से क्षतिग्रस्त हो गई थी, उन्हींको लगातार प्रयास और युद्ध स्तर पर पूर्व तट रेलवे द्वारा किये गये त्वरित बहाली कार्य के कारण केवल 16 घंटे के भीतर मरम्मत की गई है। पूर्व तट रेलवे के महाप्रबंधक रूप नारायण सुनकर स्वयं मरम्मत कार्य की निगरानी के लिए खुदा रोड रेलवे मंडल के मंडल रेल प्रबंधक सहित पूर्व रेलवे के विभागों के अन्य प्रधान प्रमुखों के साथ दुर्घटनास्थल पर थे। पुनरुद्धार कार्य के दौरान महाप्रबंधक के साथ रेलवे के मुख्य मंडल प्रमुख और खुदा रोड रेलवे जोन के मंडल रेल प्रबंधक मौजूद रहे और कार्य का निरीक्षण किया। हावड़ा-चेन्नई मुख्य



लाइन, भद्रक-कपिलास रोड रेल खंड पर, कोरई स्टेशन पर एक पण्यबहि ट्रेन के पटरी से उतरने से दोनों लाइनें क्षतिग्रस्त हो गईं और ट्रेन संचालन बाधित हो गया। पूर्व तट रेलवे द्वारा बचाव कार्यों के लिए तत्काल एक दुर्घटना राहत ट्रेन और एक दुर्घटना राहत चिकित्सा दल को तैनात किया

गया था। रेलवे के जारी प्रयासों से प्रभावित वैगनों को शाम 5.35 बजे के भीतर ट्रेन ट्रेक से बाहर किया गया था। जिससे डाउन लाइन को कम समय में कार्यकारी करने के लिए अनुमति मिला था। उसी तरह मध्य राती से पहले ही दोनों पटरियों को रेल यातायात के लिए साफ कर दिया गया दोनों

# तत्काल सौंपी गयी पीड़ितों के परिजनों को अनुग्रह राशि महाप्रबंधक ने घटनास्थल पर मरम्मत कार्य की स्वयं की निगरानी



**आजाद सिपाही संवाददाता**  
**भुवनेश्वर।** सोमवार को सुबह मालगाड़ी के पटरी से उतरने से क्षतिग्रस्त हुई कोरई की प्रभावित रेल लाइन को युद्ध स्तर पर लगातार एवं त्वरित प्रयास से पूर्व तट रेलवे द्वारा केवल 16 घंटे के भीतर बहाल कर दिया गया। पूर्व

तट रेलवे के महाप्रबंधक रूप नारायण सुनकर ने स्वयं दुर्घटना स्थल पर उपस्थित रह कर मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया। इस अवसर पर खोरधा रोड रेलवे मंडल के मंडल रेल प्रबंधक सहित पूर्व तट रेलवे के विभिन्न विभाग के प्रमुख मरम्मत कार्य की

**5-5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि भी तत्काल प्रदान की**  
इसके अलावा महाप्रबंधक सुनकर ने घटना में मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को 5-5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि भी तत्काल प्रदान की। घायलों को अनुग्रह राशि भी सौंपी गई। रेल मंत्री ने इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया था और तत्काल अनुग्रह राशि की घोषणा की थी। मृतक के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये, गंभीर रूप से घायल होने पर एक-एक लाख रुपये और मामूली रूप से घायल होने पर 25 हजार रुपये की राशि प्रभावितों को तत्काल प्रदान की गई।

निगरानी के लिए दुर्घटना स्थल पर थे। मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने के कारण, हावड़ा-चेन्नई मुख्य लाइन में भद्रक-कपिलास रोड रेलवे सेक्शन में कोरई स्टेशन पर दोनों लाइनें अवरुद्ध हो गई थीं। इसके तुरंत बाद दुर्घटना राहत ट्रेन और दुर्घटना राहत चिकित्सा दलों को बहाली के काम में लगाया गया। रेलकर्मियों के लगातार प्रयासों से प्रभावित वैगनों को शाम करीब 5.35 बजे

# वेदांता एल्युमीनियम एक्सट्रूजन उद्योग की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मास्टरक्लास का परिचालन किया

**आजाद सिपाही संवाददाता**  
**भुवनेश्वर।** नयी दिल्ली वेदांता एल्युमीनियम भारत के सबसे बड़े एल्युमीनियम उत्पादक, उन्होंने एक्सट्रूजन उद्योग की उत्पादकता बढ़ाने के तरीकों पर एक तकनीकी मास्टरक्लास का आयोजन किया। जिसमें एक्सट्रूजन सेगमेंट में लगभग 60 अग्रणी खिलाड़ियों के करीब 300 प्रतिभागी शामिल थे, जो भारत, यूएस, यूके, पुर्तगाल, ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल और कई अन्य देश के थे। एक्सट्रूजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग एक निश्चित क्रॉस-सेक्शन प्रोफाइल की वस्तुओं को ड्राई के माध्यम से सामग्री को धक्का देकर उत्कृष्ट सतह और उन्नत डिजाइन तैयार करता है। मास्टरक्लास का संचालन दुनिया के अग्रणी एक्सट्रूजन विशेषज्ञों में से एक श्री जोनाथन पैंगबॉ द्वारा किया गया था, जो कंपनी के ग्राहक तकनीकी सेवा (सीटीएस) सेल के लिए बिलेट एक्सट्रूजन के तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। मास्टरक्लास ग्राहकों के लिए वेदांता एल्युमीनियम की ढेरों पेशकशों का हिस्सा था, जिसमें नये उत्पाद का विकास, नये अनुप्रयोग विकास, बाजार विकास, ज्ञान और तकनीकी विशेषज्ञता और भारत के प्रमुख तकनीकी विश्वविद्यालयों और संस्थानों के छात्रों ने भी सत्र में भाग लिया। एल्युमीनियम आज दुनिया की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण धातु है, जिसमें उच्च शक्ति-से-वजन अनुपात, असाधारण डिजाइन लचीलापन, संक्षारण-प्रतिरोध, विद्युत चालकता और शाश्वत पुनर्चक्रण जैसे अद्वितीय



गुण हैं। एल्युमीनियम के इन बहुमुखी गुणों को बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए

एक्सट्रूजन प्रक्रिया की बहुमुखी प्रतिभा द्वारा पूरक किया जा सकता है। एल्युमीनियम की क्षमता किसी भी आकार में निकाली जा सकती है-चाहे कितनी भी जटिल हो, सख्त सहनशीलता के साथ, यह डिजाइन अनुप्रयोगों के लिए एक आदर्श सामग्री बनती है जिसके लिए क्रॉस-विभाग क्षेत्र से अधिकतम बहुमुखी प्रतिभा की आवश्यकता होती है। वेदांता लिमिटेड का एक व्यवसाय वेदांता एल्युमीनियम भारत का सबसे बड़ा एल्युमीनियम उत्पादक है, जो वित्त वर्ष 2022 में भारत के आधे से अधिक एल्युमीनियम यानी 2.26 मिलियन टन का निर्माण करता है। यह मूल्य वर्धित एल्युमीनियम उत्पादों में अग्रणी है जो मुख्य उद्योगों में महत्वपूर्ण अनुप्रयोग पाते हैं।

# एमसीएल ने किया जूट बैग का वितरण

**आजाद सिपाही संवाददाता**  
**संबलपुर।** महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) ने लोगों को प्लास्टिक की थैलियों को नुकाने तथा छोड़ने और पर्यावरण को देखभाल करने के लिए प्रेरित करने के लिए परिधीय घरों में जूट बैग वितरित करके 'एकल उपयोग प्लास्टिक' के उपयोग को कम करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। इस जागरूकता अभियान के पहले चरण में एमसीएल संबलपुर के लोगों में 10,000 जूट बैग वितरित करने की योजना बनाई है। कंपनी अपने एमसीएल के पर्यावरण और वन विभाग के



माध्यम से स्वच्छ पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने तथा लोगों के बीच जूट बैग वितरण करने के लिये विभिन्न स्थानों पर सूचना

शिविरों का आयोजन कर रही है। इस अभियान के तहत लोगों तथा विशेषकर छात्रों के समुदाय में उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है।

उत्कृष्टता के 30 वर्षों का जश्न मनाते हुए, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), भारत सरकार की एक 'मिनी-रत्न' कंपनी ने ओडिशा के अंगुल, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़ और संबलपुर जिलों में फैले अपने कमांड क्षेत्रों में तथा उसके आसपास 6.5 मिलियन से अधिक पौधे लगाये हैं।

# मुख्यमंत्री ने हॉकी विश्व कप का पहला टिकट फिलिप तिर्की से लिया

**आजाद सिपाही संवाददाता**  
**भुवनेश्वर।** ओडिशा में 2023 हॉकी विश्व कप का आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए तैयारियां खूब तेजी से चल रही हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने हॉकी विश्व कप का पहला टिकट लिया। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलिप तिर्की से टिकट प्राप्त किया। हॉकी विश्व कप जनवरी 2023 से कलिंग स्टेडियम में शुरू होगा। इससे पहले 8 सितंबर को मुख्यमंत्री ने हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल जारी किये थे। गौरतलब है कि हॉकी विश्व कप भुवनेश्वर और राउरकेला में खेला जाने वाला है। इसलिए



राज्य सरकार ने पूरी तैयारी तेज कर दी है। राउरकेला और भुवनेश्वर में हॉकी स्टेडियमों को पूरी तरह तैयार कर लिया गया है। 2023 हॉकी विश्व कप में 16 टीमों 4 पूल में खेलेगी। पूल ए में-ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, फ्रांस,

दक्षिण अफ्रीका, जबकि पूल बी में- बेल्जियम, जर्मनी, कोरिया, जापान रहा है। इसके अलावा पूल सी में नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, मंगेशिया और चिली है, पूल डी में भारत, इंग्लैंड, स्पेन और वेल्स हैं।

**study MBBS in ABROAD**  
RUSSIA GEORGIA POLAND EGYPT  
KAZHAKASTAN UZBEKISTAN  
Get Direct Admission in  
Top Government Medical Universities  
of/ABROAD.  
Call Now!  
UNIVERSITY FLY  
+91-7903149721  
www.universityfly.com

**VERMA PRESS**  
**वर्मा प्रेस प्रा० लि० राँची**  
शृंखला की निम्न पुस्तकें सर्वत्र उपलब्ध हैं—  
Based on JCERT  
**Class - VIII**  
Class VIII Today (Combined) ₹ 250  
Class VIII Today (English Medium) ₹ 280  
Mathematics Practical ₹ 60  
Science Practical ₹ 60  
S. Science Practical ₹ 60  
Hindi Vyakaran-I ₹ 60  
English Grammar-I ₹ 60  
Sanskrit Vyakaran-I ₹ 50  
**Classes VI & VII**  
Class VII Today (Combined) ₹ 240  
Class VII Today (Combined) ₹ 240  
Hindi Vyakaran-I ₹ 60  
English Grammar-I ₹ 60  
Sanskrit Vyakaran-I ₹ 50  
मिलते-जुलते नाम वाली नकली पुस्तकों से सावधान!

**DADI PLASTIC & KITCHENWARE**  
Home & Kitchen  
Deals in : Specially in Plastic & Cleaning  
(WHOLESALE & RETAIL)  
MILTON, CELLO, BFW, ARISTO, TECHNO, DEEPAK, PARAS, CUBO  
North Market Road, Upper Bazar, Ranchi - 834001 (Jharkhand) Mob. : 9693000799, 7979703432

**रत्न विक्रेता जय माता दी रत्न विक्रेता**  
**ज्योतिष ग्रहर्त्न केन्द्र**  
ज्योतिष शास्त्र • वास्तु शास्त्र • हस्त शास्त्र • हस्त रेखा • अंक शास्त्र  
पंडित शशि कान्त मिश्रा  
पता - लाईन टैंक रोड, गोपाल गंज गली, अपोजिट-भूतपूर्व बारगेन बाजार, रांची  
फोन :- 9334718296, 9835195382, 9431792761

**अविराम ए ग्रुप ऑफ इंस्टीटयुशंस**  
(मान्यता एवं संबद्धता रांची वि.वि., जेक, एनपीयू, पी.सी.आई., JSPC, JNRC एवं चिह्नित NCTE भुवनेश्वर उड़ीसा)  
टिको, कुडू, लोहरदगा एवं हुटाप, चंदवा, लातेहार (झारखंड)  
इंटर एवं स्नातक पास बालक/बालिकाएं शोध प्रवेश एवं B.ed के अतिरिक्त अन्य में सीधे प्रवेश हेतु आवेदन करें  
झारखंड स्टेट एवं रांची विश्वविद्यालय में टॉपर देने वाले संस्थान में प्रवेश का सुनहरा अवसर  
E.A.N.M A.N.M डी.फार्मसी D.Pharmacy बी.एड. B.Ed. बी.एस.सी. नर्सिंग B.Sc Nursing डी.एल.एड D.El.Ed  
FACILITIES : SCHOLARSHIP • BUS & HOSTEL FACILITY  
CAMPUS PLACEMENT • WELL EQUIPPED LAB • ONLINE ADMISSION PAYMENT & ONLINE CLASS FACILITY  
URGENT REQUIREMENT  
B. Sc Nursing/ M.Sc Nursing Pass  
D. Pharma/ B. Pharmacy Pass  
B.Ed & M.ed in (Science/Literature Social Science)  
Send resume within 3 days in 7782054270  
संपर्क क्रॉजिए : 7782054270, 8987470640 | www.aviramcollege.com, www.aviramcollegeofnursing.com  
bedcollege2011@gmail.com/aviram.gv@gmail.com